बारा विधायक डॉ. वाचस्पति की पहल से बदली विकास की राह

अशोका एक्सप्रेस

Member : CNSI, Delhi निर्वाण प्राप्त गीता भारती राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

Website :-www.ashokaexpress.com YouTube ashokaexpress

E-mail :-ashoka.express@live.com ashokaexpress

संपादक :- विजय कुमार भारती
प्रबंधक :- सज्जन सिंह

● वर्षः 29 ● अंक : 08 ● नई दिल्ली ● 01 से 08 मार्च 2026 ● पृष्ठ : 8 ● मूल्य : 2 रूपये

बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल..., केजरीवाल के बरी होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का निशाना

नई दिल्ली । कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव द्वारा शनिवार (28 फरवरी) को जारी किए गए एक बयान ने दिल्ली की राजनीति में नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद अरविंद केजरीवाल बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर खुद को पाक-साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. देवेंद्र यादव ने आगे कहा कि यह मॉडल बताता है कि सत्ता के सामने झुकते ही आरोपों के दाग हल्के पड़ने लगते हैं. उनके मुताबिक यह देश की राजनीति में दोहरे मापदंड और जांच एजेंसियों के चयनात्मक इस्तेमाल को उजागर करता है. देवेंद्र यादव ने याद दिलाया कि 3 जून 2022 को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत में पंजाब के अकाली दल के नेता दीप मल्होत्रा का नाम लेते हुए शराब नीति से जुड़े गंभीर सवाल उठाए गए थे. उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के संभावित समीकरणों की चर्चा के बीच यह मामला और भी प्रासंगिक हो जाता है. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उस समय तात्कालीन उपरायपाल की भूमिका और मास्टर प्लान के उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया गया था. हालांकि इस पर न तो कोई स्पष्ट जवाब मिला और न ही जांच एजेंसियों ने इस दिशा में ठोस कार्रवाई की. उनका कहना है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया गया. यादव के मुताबिक 5 सितंबर 2022 को दिल्ली कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस के पास गया था. प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी के खाते में शराब घोटाले से जुड़ी कंपनी सोम ग्रुप द्वारा 2 करोड़ रुपये के चंदे से जुड़े दस्तावेज सौंपे थे और जांच की मांग की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि जांच निष्पक्ष होती तो बीजेपी के बड़े नेता और केजरीवाल दोनों कानून के दायरे में होते. इसके विपरीत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई चुनावी जरूरतों से प्रभावित प्रतीत होती है. देवेंद्र यादव ने कहा कि देश में एक खतरनाक प्रवृत्ति विकसित हो रही है, जहां सत्ता के

सामने सरेंडर करने पर आरोप कमजोर पड़ते दिखाई देते हैं. उन्होंने दावा किया कि गुजरात और पंजाब में केजरीवाल का राजनीतिक उपयोग करने की कोशिशें दिख रही हैं. वहीं तमिलनाडु में चुनावी माहौल के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को परेशान करने की तैयारी भी इसी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होती है.

राउज एवेन्यू कोर्ट और कैग रिपोर्ट का किया जिक्र

यादव ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कथित नूराकुश्ती के संकेत राउज एवेन्यू कोर्ट की कार्यवाही से सामने आए, जहां सीबीआई कथित तौर पर ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई. उन्होंने कहा कि केजरीवाल से जुड़ी 14 कैग रिपोर्टों पर कार्रवाई न होना भी गंभीर सवाल खड़े करता है. ट्रायल कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर आरोप खारिज किए जाने के बाद यादव ने सवाल उठाया कि जब डॉ. मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और शीला दीक्षित पर आरोप लगाए गए थे तब केजरीवाल की संवेदनाएं कहां थीं. उनका आरोप है कि राजनीतिक लाभ के लिए मीडिया ट्रायल और बदनाम करने का अभियान चलाया गया.

ईडी-सीबीआई पर साधा निशाना

यादव ने कहा कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल शतरंज के मोहरों की तरह करती है. उन्होंने आरोप लगाया कि जहां चुनाव होते हैं, वहीं ईडी और सीबीआई की सक्रियता बढ़ जाती है. इस राजनीतिक रणनीति में राहुल गांधी लगातार निशाने पर रहते हैं, जबकि अन्य नेताओं को परिस्थितियों के अनुसार ÷काला या सफेद÷ किया जाता है.

शराब नीति को लेकर भी उठाए सवाल

दिल्ली कांग्रेस ने शराब नीति से जुड़े कई प्रश्न फिर उठाए. उन्होंने पूछा कि यदि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह ईमानदार थे तो अनियमितताओं के संकेत मिलते ही नीति वापस लेकर बदलाव क्यों किया गया. कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड नष्ट क्यों किए गए.

कमीशन 6 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत क्यों किया गया. उन्होंने कहा कि ये सवाल कल्पना पर आधारित नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से सामने आए तथ्यों पर आधारित हैं. ÷एक पर एक फ्री÷ जैसी योजनाओं के सामाजिक प्रभाव और शराब पीने की आयु कम करने के फैसले को भी उन्होंने गंभीर चिंता का विषय बताया. यादव ने कहा कि दिल्ली आबकारी मामले में आया फैसला निचली अदालत का है. उन्होंने कहा कि अतीत में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मामलों में गंभीर टिप्पणियां की हैं. ऐसे में यह देखना बाकी है कि यह फैसला उच्च अदालतों में कितना टिक पाता है. कानूनी प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है.

न्यायपालिका और विद्यार्थी !

भारत की स्वतन्त्रता के बाद हमने जिस संवैधानिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था को अपनाया उसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका व चुनाव आयोग का ऐसा चौखम्भा तन्त्र था जिसकी बुनियाद पर पूरी व्यवस्था खड़ी होती थी। इसमें भी हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका व चुनाव आयोग को सरकार का अंग नहीं बनाया और सुनिश्चित किया कि भारत का संविधान इस देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को जो एक वोट का अधिकार देता है, उसके आधार से बहुमत से बनी सरकार सर्वदा संविधान के प्रति ही उत्तरदायी रहे , जिसकी जिम्मेदारी न्यायप्रणाली को दी गई। अतः भारत में स्वतन्त्र , निष्पक्ष व 'अराजैतिक' न्यायप्रणाली के जरिये प्रत्येक राजनैतिक दल पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि वह बहुमत के आधार पर सत्ता में आने पर पूरी लोकतान्त्रिक प्रणाली को केवल संविधानोन्मुख ही बनाये रखे। विधायिका को संविधान में संशोधन करने व नये कानून बनाने का अधिकार देने के साथ ही न्यायपालिका को ऐसे सभी कृत्यों को संविधान की कसौटी पर कसने की छूट केवल इसलिए दी गई जिससे किसी भी परिस्थिति में भारत में संविधान के शासन की उल्लंघना न हो।

इस नजरिये से देखें तो भारत के लोकतन्त्र में न्यायपालिका का स्थान ऐसे पवित्र स्थल के रूप में निरूपित हुआ जिसके समक्ष प्रत्येक राजनैतिक दल की सरकार को अपने कामों की सफाई देनी होती है। अतः न्यायपालिका की प्रक्रियागत व्यवस्था में जिन खामियों की चर्चा कक्षा आठ के पाठ्यक्रम में शामिल 'न्यायपालिका और भ्रष्टाचार' के अध्याय में की गई है वह पूरी तरह से बेमानी और बदनीयती से प्रेरित है क्योंकि ऐसा करके अध्याय के लेखकों ने इस कक्षा में पढ़ने वाले बालमन में लोकतन्त्र की शुद्धता के प्रति प्रारम्भ से ही सशंकित होने का भाव जगाने का काम कर डाला है। यह सौभाग्य की बात है कि इसका संज्ञान स्वयं देश की सर्वोच्च अदालत ने लिया और पाठ्य पुस्तक प्रकाशित करने वाली संस्था राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान परिषद (एनसीईआरटी) व शिक्षा मन्त्रालय को नोटिस जारी किया तथा पुस्तक के किसी भी प्रकार को प्रचार ड्ड प्रसार पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस पुस्तक को अब कक्षा आठ के पाठ्यक्रम से वापस ले लिया गया है परन्तु असली सवाल यह है कि सरकारी नियन्त्रण में चलने वाली संस्था एनसीईआरटी द्वारा इस प्रकार का प्रयास क्यों किया गया जिसे सभी सरकारी मंचों से स्वीकृति भी मिल गई। कक्षा आठ के सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में भारत की लोकतान्त्रिक व्यवस्था के विभिन्न अवयवों के बारे में छात्रों को ज्ञान दिया जाता है अतः उन्हें केवल उस प्रणाली के बारे में ही ज्ञान देना जरूरी होता है जिसके आधार पर इस देश की शासन व्यवस्था चलती है।

इसकी प्रक्रियागत रूप रेखा के गुण दोषों को जानने का अवसर विद्यार्थियों को ऊंची कक्षाओं में जाकर प्राप्त होता है । ऊंची कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों को पता चलता है कि वे जिस व्यवस्था में जी रहे हैं उसमें किस प्रकार विभिन्न खामियों का प्रवेश हो चुका है मगर शुरू में ही विद्यार्थियों को यदि बता दिया जाये कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस स्वतन्त्र न्याय प्रणाली की स्थापना की है। वह अपना कार्य पवित्रता से करने में अक्षम है तो इससे बालमन में उस संस्था के प्रति हेय दृष्टि विकसित होती है जिससे समूचे समाज व राष्ट्र में उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। अतः प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस बारे में प्राथमिक जानकारी लेने की खबर को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा मन्त्री से पूछा कि पाठ्यक्रम बनाने का काम कौन देख रहा है ? जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है तो यह सर्वव्यापि व्याधि है जिससे अब शासन का कोई भी अंग मुक्त नहीं समझा जा सकता लेकिन यह भी सच है कि सर्वाधिक चर्चा विधायिका में ही व्याप्त भ्रष्टाचार की होती है। इसका सीधा सम्बन्ध देश की राजनीति से होता है। पूरे भारत के लोग जानते हैं कि किस प्रकार 2014 तक चली मनमोहन सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते ही देश की जनता ने उसे सत्ता से बाहर किया। मगर इसका मतलब यह कहां निकलता है कि हमारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया गया है? क्या हम अपने विद्यार्थियों को यह पढ़ा सकते हैं कि भारतीय लोकतन्त्र का सबसे अहम व सर्वोच्च स्तम्भ 'विधायिका' भ्रष्टाचार की वजह से खोखला हो चुका है। इसी प्रकार कार्यपालिका के भ्रष्टाचार के बारे में भी नागरिक जैसे -जैसे बड़े होते जाते हैं वैसेड्डवैसे ही विभिन्न सूचना माध्यमों से जाने जाते हैं। मगर जब हम किसी विद्यार्थी को प्रारम्भिक कक्षाओं में देश की शासकीय प्रणाली में बताते हैं तो उसे आधारभूत अवयवों की शिक्षा ही देते हैं। जाहिर है कि जब विद्यार्थी ऊंची कक्षाओं में जायेंगे तो इनके प्रक्रियागत दोषों के प्रति स्वयं ही शिक्षा ग्रहण करते हुए जानेंगे। अतः एनसीईआरटी ने न्यायपालिका को लेकर जिस प्रकार का नजरिया अपनाया वह भारत की लोकतान्त्रिक व्यवस्था को पूरी तरह शर्मसार करने वाला था। मगर ऐसा करके इस संस्था ने खुद की ही विश्वसनीयता को सन्देह के घेरे में खड़ा कर दिया है क्योंकि इससे यही सिद्ध होता है कि इसका संचालन करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्हें यह तक नहीं पता कि उनकी इस देश के विकास में क्या भूमिका है। किसी भी देश का विकास उसके नागरिकों द्वारा ही किया जाता है। यदि इन नागरिकों के मन में बालपन से ही यह बीज बो दिया जायेगा कि वे जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वह मानवीय कमजोरियों की वजह से बंजर बन चुकी है तो फिर उसमें अच्छा नागरिक बन कर व्यवस्था को सुधारने का जज्बा खत्म होने लगेगा। इससे उसके जीवन के आदर्श बदलने लगेंगे । हमे नहीं भूलना चाहिए कि भारत वह देश है जिसमें सम्राट विक्रमादित्य के 'आसन' को न्याय का सिंहासन मानने की कथाएं आज भी प्रचिलित हैं। स्वतन्त्र भारत में न्यायपालिका का इतिहास भी कमोबेश इसी मान्यता के इर्द- गिर्द घूमता भी रहा है।

सम्पादकीय

संजय सिंह का पासपोर्ट

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के सामने अजीब स्थिति है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें नए बनाए गए पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स में से एक को लीड करने के लिए नियुक्त किया है। वह उस ग्रुप के चेयरपर्सन हैं जिसे कैरेबियन देशों में गुडविल मिशन पर भेजा जा रहा है। असल बात यह है कि संजय सिंह के पास पासपोर्ट नहीं है। 2023 में दिल्ली एक्साइज केस में गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने इसे दिल्ली हाई कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उन्हें 2024 में बेल पर रिहा किया गया लेकिन उनका पासपोर्ट खो गया और उन्हें 2 लाख रुपये का बॉन्ड भरना पड़ा। यह हैरानी की बात है कि लोकसभा सचिवालय, जिसने स्पीकर को बनाए जा रहे कई फ्रेंडशिप ग्रुप्स के लिए सांसदों की लिस्ट बनाने में मदद की थी, उसे संजय सिंह के पासपोर्ट का स्टेटस नहीं पता था। न ही उसने लिस्ट में उनका नाम जोड़ने से पहले चेक किया, वह भी कैरेबियन देशों में भेजे जा रहे डेलीगेशन के चेयरपर्सन के तौर पर। आप सांसद इसे बेइज्जती के तौर पर देखते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार उनका पासपोर्ट वापस दिलाने के लिए कोर्ट जाएगी या फिर लिस्ट से उनका नाम हटाने जैसा शर्मनाक कदम उठाएगी। या उनके बॉस अरविंद केजरीवाल और आप के साथी मनीष सिसोदिया की तरह, सिंह भी सबूतों की कमी के कारण अपने खिलाफ लगे आरोपों से बरी हो गए हैं और उनको पासपोर्ट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जहां तक ??केजरीवाल और सिसोदिया की बात है, शायद उन्हें अब अधिकारियों पर मानहानि और मानसिक परेशानी का केस करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने उनकी इज्जत और ईमानदारी वापस दिला दी है। यह दिलचस्प है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में ?अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के बावजूद 60 देशों में सांसदों की टीमों को गुडविल विजिट पर भेजने का फैसला किया। बेशक, अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा क्योंकि विपक्ष के पास इसे पास कराने के लिए नंबर नहीं हैं। लेकिन यह बिरला के लिए परेशानी भरा है क्योंकि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संसद के इतिहास में बहुत कम होता है। पॉलिटिकल हलकों में बिरला के इन तथाकथित पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स को बनाने और उन्हें विदेश में अलग-अलग समूह भेजने के कदम से हैरानी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने सांसदों की टीमों को विभिन्न देशों में भेजा था। लेकिन उस समय सांसदों को विदेशों में भेजना समझ में आता है क्योंकि भारत पहलगाम टेरर स्ट्राइक और उसके बाद हुए सैन्य टकाराव के बाद पाकिस्तान के अनर्गल प्रचार से निपटने के लिये वह जरूरी था। हालांकि, आज, ऐसा लगता है कि यह बहुत ज़रूरी है। अब यह सवाल उठ रहा है कि विभिन्न दलों के सांसदों को विदेशों में क्यों भेजा जा रहा है। राजनीतिक हलकों में कुछ लोगों को लगता है कि यह बजट सेशन के पहले हिस्से में लोकसभा स्पीकर की नकारात्मक पब्लिसिटी को बेअसर करने की कोशिश है। विपक्ष उनसे तब भिड़ गया जब उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम एम नरवणे की विवादित अप्रकाशित किताब पर बोलने से रोक दिया था।

वोट के लिए मुफ्त की रेवड़ी से कर्जे के अंधकूप में देश

आलम यह है कि हिमाचल सरकार के पास लिए गए कर्ज की मूल रकम व उस पर लगने वाले ब्याज को चुकाने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। वहीं, कर्ज लेने की लिमिट सिर्फ 10 हजार करोड़ रुपए है। अगले वित्तीय वर्ष में कर्ज व ब्याज चुकाने के लिए 13 हजार करोड़ चाहिए। अब लोन को चुकाने के लिए मार्केट से कर्ज लेकर भी बात नहीं बन रही और तीन हजार करोड़ रुपए अपने बजट से चुकाने होंगे। सोलहवें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में हिमाचल सहित अन्य कुछ रायों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) खत्म कर दी है। इससे हिमाचल सरकार के खजाने पर भारी चोट लगी है। हिमाचल प्रदेश पर कुल देनदारियां 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई हैं, जिससे यह पहाड़ी राय कर्ज लेने वाले भारतीय रायों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट (2025-26) में कहा है कि मुफ्त की ऐसी योजनाओं के चलते रायों के बजट पर दबाव बढ़ रहा है। हरियाणा और पंजाब जैसे रायों में बुनियादी ढांचे (सड़क, स्कूल, अस्पताल) पर खर्च कुल बजट का 10ब से भी कम रह गया है। मुफ्त की रेवड़ी बांटने में कोई पीछे नहीं है। केंद्र में बतौर विपक्षी पार्टी आलोचना करने वाली कांग्रेस अपनी सत्ता वाले रायों में खुल कर रेवड़ियां बांटती रही है। उसी तरह केंद्र में खुल कर यह काम करने वाली भाजपा, रायों में कांग्रेस व अन्य पार्टियों का इसके लिए विरोध करती है।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से-तुंग ने कहा था कि किसी आदमी को एक मछली दो और तुम उसे एक दिन के लिए खिलाओगे। उसे मछली पकड़ना सिखाओ और तुम उसे ज़िंदगी भर खिलाओगे। आज के भारतीय शब्दों में यह है कि हर नेता जो मुफ्त चीजों का वादा करता है, असल में यह कह रहा है कि मैं तुम्हें एक अछी रोजी-रोटी और रेगुलर इनकम की इजत नहीं दे सकता। इसलिए अभी के लिए यह कुछ है, इसी से काम चला लो। चुनाव आते ही मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए राजनैतिक दलों में मुफ़्त की रेवड़ी बाँटने की होड़ लग जाती है। कोई मुफ़्त बिजली और पानी देने की बात करता है तो कोई स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, साइकिल और टीवी की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाएं देने की संस्कृति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि देश के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाली ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक याचिका दायर कर उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति पर गौर किए बिना हर किसी को निःशुल्क बिजली प्रदान करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, कोर्ट ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) सरकार के नेतृत्व वाली बिजली वितरण कंपनी की मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है। बिजली वितरण कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में विद्युत संशोधन नियम, 2024 के एक नियम को चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मुफ्त की चीजें देकर राय सरकारें लोगों की आदतें खराब कर रही है।

कोर्ट ने आगे कहा कि इन लोगों का रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कई राय सरकारें कर्ज और घाटे से दबी हुई हैं। इसके बावजूद वे मुफ्त योजनाएं बांट रही हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने पूछा कि बिजली शुल्क अधिसूचित होने के बाद तमिलनाडु की कंपनी ने अचानक जेब ढीली करने का फैसला क्यों किया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा रायों को रोजगार के रास्ते खोलने के लिए काम करना चाहिए। अगर आप सुबह से शाम तक मुफ्त भोजन देना शुरू कर देंगे, फिर मुफ्त साइकिल, मुफ्त बिजली देंगे, तो कौन काम करेगा और फिर कार्य संस्कृति का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि वैलफेयर के तौर पर आप उन लोगों को देना चाहते हैं जो बिजली का चार्ज नहीं दे सकते, लेकिन जो लोग खर्च उठा सकते हैं और जो नहीं उठा सकते, उनके बीच फर्क किए बिना, आप बांटना शुरू कर देते हैं। तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था। इसमें अनुमान के मुताबिक, राय का कुल बकाया कर्ज बढ़कर 10.71 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

इस बढ़ते कर्ज के लिए वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु ने केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र तमिलनाडु में वित्तीय अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मंजूरी नहीं दे रही है और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का फंड रोक रही है। उन्होंने जीएसटी दरों में कटौती और 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पर भी निराशा जताई। मंत्री थेन्नारसु के अनुसार संघीय ढांचे में रायों के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार पहले कभी नहीं देखा गया। द्रमुक (डीएमके) सरकार ने अपनी फ्लैगशिप योजनाओं के लिए फंड की कमी नहीं होने दी। महिलाओं के लिए 'विदियाल पयानम' योजना (मुफ्त बस यात्रा) के लिए 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इसके अलावा, छात्रों के लिए बस किराए की योजना हेतु 1,782 करोड़ रुपये और डीजल सब्सिडी के लिए 1,857 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर परिवहन विभाग को 13,062 करोड़ रुपये मिले। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी सरकार ने 5,463 करोड़ रुपये का बड़ा हिस्सा अलग रखा है। तमिलनाडु में पिछले 4 वर्षों में प्रति परिवार कर्ज तेजी से बढ़कर लगभग 3.7 लाख रुपए तक पहुंच गया है, जो राय की गंभीर वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु पर देश में सर्वाधिक 8.34 लाख करोड़ रुपये कर्ज है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। इस पर 7.69 लाख करोड़ रुपये कर्जा है।

इसी तरह महाराष्ट्र पर 7.22 लाख करोड़, पश्चिम बंगाल पर 6.58 लाख करोड़ रुपये, कर्नाटक पर 5.97 लाख करोड़ रुपये, राजस्थान पर 5.62 लाख करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश पर 4.85 करोड़ रुपये का कर्जा है। गुजरात पर 4.67 लाख करोड़ रुपये, केरल पर 4.29 लाख करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश पर 4.18 लाख करोड़ रुपये, तेलंगाना पर 3.89 लाख करोड़ रुपये, पंजाब पर 3.51 लाख करोड़ रुपये, हरियाणा पर 3.36 लाख करोड़ रुपये, बिहार पर 3.19 लाख करोड़ रुपये और असम पर 1.51 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। वर्ष 2016-17 के बाद कर्ज पर निर्भरता लगातार बढ़ती गई। वोट बैंक की राजनीतिक के कारण ऐसी लोकलुभावन मुफ्त की योजनाओं के कारण छोटा पहाड़ी राय हिमाचल प्रदेश डेब्ट ट्रैप में फंस गया है। आलम यह है कि हिमाचल सरकार के पास लिए गए कर्ज की मूल रकम व उस पर लगने वाले ब्याज को चुकाने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। वहीं, कर्ज लेने की लिमिट सिर्फ 10 हजार करोड़ रुपए है। अगले वित्तीय वर्ष में कर्ज व ब्याज चुकाने के लिए 13 हजार करोड़ चाहिए। अब लोन को चुकाने के लिए मार्केट से कर्ज लेकर भी बात नहीं बन रही और तीन हजार करोड़ रुपए अपने बजट से चुकाने होंगे। सोलहवें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में हिमाचल सहित अन्य कुछ रायों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) खत्म कर दी है। इससे हिमाचल सरकार के खजाने पर भारी चोट लगी है। हिमाचल प्रदेश पर कुल देनदारियां 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई हैं, जिससे यह पहाड़ी राय कर्ज लेने वाले भारतीय रायों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट (2025-26) में कहा है कि मुफ्त की ऐसी योजनाओं के चलते रायों के बजट पर दबाव बढ़ रहा है। हरियाणा और पंजाब जैसे रायों में बुनियादी ढांचे (सड़क, स्कूल, अस्पताल) पर खर्च कुल बजट का 10ब से भी कम रह गया है। मुफ्त की रेवड़ी बांटने में कोई पीछे नहीं है। केंद्र में बतौर विपक्षी पार्टी आलोचना करने वाली कांग्रेस अपनी सत्ता वाले रायों में खुल कर रेवड़ियां बांटती रही है। उसी तरह केंद्र में खुल कर यह काम करने वाली भाजपा, रायों में कांग्रेस व अन्य पार्टियों का इसके लिए विरोध करती है। बीते नौ साल में प्रति व्यक्ति कर्ज तीन गुना बढ़ गया है। इसका एक बड़ा कारण केंद्र व राय सरकारों द्वारा जनता को खुले आम रेवड़ियां बांटना भी है। देश में प्रति व्यक्ति कर्ज 1,86,206 रुपए हो जाने का अनुमान है। अहम बात यह है कि राजनीतिक दलों को यह भी बताना चाहिए कि इन मुफ्त की योजनाओं के लिए धन कहां से आएगा। अब हमारी फाइनेंशियल पॉलिटिक्स में ईमानदारी और जवाबदेही वापस लाने का समय आ गया है।

स्वामी, प्रकाशक वं मुद्रक विजय कुमार ने अशोक सम्राट प्रिन्टर्स, 215, पीरागढ़ी गांव, दिल्ली-87 से मुद्रित कर बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086 प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार। (RNI No. 70098/99) इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी हैं। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगें। **Phone : 9810674206**

ऊर्जा निगमों में असली जंग टेक्नोक्रेट बनाम ब्यूरोक्रेट, राज्य सरकारें नहीं तलाश सकीं कोई समाधान; बढ़ी गुटबाजी

देहरादून। उत्तराखंड में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखंड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद से गैर तकनीकी पृष्ठभूमि के प्रकाश चंद्र ध्यानी को कार्यमुक्त करने का मुद्दा गर्म है। ध्यानी को हटाने के कई सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं, लेकिन यह मामला सिर्फ पीसी ध्यानी तक सीमित नहीं बल्कि देश भर के ऊर्जा निगमों में शीर्ष पदों को लेकर छिड़ी टेक्नोक्रेट बनाम ब्यूरोक्रेट की जंग का एक हिस्सा है। उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों के ऊर्जा निगमों में यह टकराव चल रहा है। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या राज्य सरकारें पारदर्शी और स्पष्ट चयन प्रक्रिया अपनाकर इस बहस को समाधान तक पहुंचाएंगी, या तकनीकी बनाम प्रशासनिक गुटबाजी का यह स्वर और तीखा होता जाएगा। उत्तराखंड में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी की पात्रता पर सवाल उठा तो शासन को व्यवस्था में बदलाव करना पड़ा। कार्यमुक्त होने से पीसी ध्यानी का विवाद तो थम गया है, लेकिन यह टकराव समाप्त नहीं हुआ है। इंजीनियर संगठनों का कहना है कि ग्रिड संचालन, ट्रांसमिशन नेटवर्क और सिस्टम संचालन तकनीकी विषय है। इसलिए शीर्ष पद पर तकनीकी पृष्ठभूमि अनिवार्य होनी चाहिए, जबकि राज्य सरकार का तर्क है कि प्रशासनिक अनुभव को नजरंदाज नहीं कर सकते। नियमों के तहत प्रशासनिक व्यक्ति को अस्थाई प्रभार दिया जा सकता है।

कई राज्यों में नेतृत्व को लेकर आमने-सामने

यह विवाद उत्तराखंड तक सीमित नहीं। पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लि. और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. में भी तकनीकी पृष्ठभूमि वाले एमडी को नियुक्त करने की मांग इंजीनियर संगठनों ने सीएम से की है।

वहां के इंजीनियर्स का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देने से तकनीकी निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. में समय-समय पर तकनीकी बनाम प्रशासनिक नेतृत्व को लेकर असंतोष सामने आता है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. में तकनीकी नेतृत्व की परंपरा बनाए रखने की मांग कर्मचारी संगठन उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी में भी तकनीकी बनाम प्रशासनिक धड़े के बीच नेतृत्व को लेकर विवाद पुराना है।

उत्तराखंड में सहकारिता आंदोलन को मिलेगा बढ़ावा, हर जिले में बनेंगे मॉडल गांव

देहरादून। प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए सरकार प्रत्येक जनपद में एक-एक माडल सहकारिता गांव स्थापित करेगी। इस महत्वाकांक्षी योजना को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए विभागीय अधिकारियों को विस्तृत रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सहकारिता मंत्री डा धन सिंह रावत ने शनिवार को शासकीय आवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि संस्कृत गांव की तर्ज पर माडल सहकारिता गांव विकसित किए जाएं। इन गांवों में सहकारी बैंक, कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) और सहकारी बाजार स्थापित किए जाएंगे। सहकारी बाजार के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों, किसान समूहों और ग्रामीण उत्पादकों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए सशक्त मंच उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना और सहकारिता आधारित आत्मनिर्भर मॉडल विकसित करना है। इससे गांवों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा। बैठक में सहकारी समितियों के 50 सचिवों को अध्ययन भ्रमण के लिए गुजरात भेजने का निर्णय भी लिया गया। इसमें नवगठित एवं प्रारंभिक अवस्था में कार्यरत समितियों के सचिवों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वे वहां के सफल सहकारी माडलों का अध्ययन कर अपने क्षेत्रों में लागू कर सकें। डा रावत ने निर्देश दिए कि होली के बाद संयुक्त निबंधक, अपर निबंधक एवं प्रभारी अधिकारी जनपदों में ब्लाक स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित करें। घाटे में चल रही समितियों को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार कर उसे लागू किया जाएगा। उन्होंने सभी पैक्स एवं एमपेक्स समितियों की नियमित बोर्ड बैठकें सुनिश्चित करने, सहकारी बैंकों में शत-प्रतिशत नियुक्तियां आईबीपीएस के माध्यम से पारदर्शी ढंग से करने तथा 15 मार्च तक भर्ती विज्ञापन जारी करने के निर्देश भी दिए। साथ ही योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय भाषाओं में करने पर जोर दिया गया। उन्होंने विश्वास जताया कि माडल सहकारिता गांव राज्य में आत्मनिर्भर एवं समावेशी ग्रामीण विकास की नई दिशा तय करेंगे।

टीम प्लेयर बनो, नहीं तो रिजर्व में बिठा देंगे, पंजाब में बोले राहुल गांधी; खेमों में बंटी कांग्रेस को दी चेतावनी

चंडीगढ़।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपसी गुटबाजी के चलते मिली हार से सबक लेते हुए कांग्रेस सासंद राहुल गांधी ने पंजाब के नेताओं को नसीहत दी है। शुक्रवार को पंजाब के बरनाला में किसान महाचौपाल के दौरान उन्होंने पंजाब की लीडरशिप को साफ संदेश दिया है कि वह अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस हाई कमान की ओर से ऐसा स्पष्ट संदेश पहले कभी भी सार्वजनिक तौर पर नहीं दिया गया।

पहले केवल दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में ही बुलाकर फटकार लगाकर भेज दिया जाता था, जिसका प्रादेशिक लीडरशिप पर कोई असर नहीं हो रहा था। यही वजह है कि पंजाब में कांग्रेस कई खेमों में बंटी हुई है। हालांकि बीच-बीच में एकजुटता की तस्वीर पेश करने की जरूर कोशिश करती दिखाई जाती है, लेकिन बात नहीं बन रही है। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी को संदेश देते हुए कहा कि काम टीम वर्क से होता है। एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता, पूरी टीम से बात बनती है। इसलिए टीम प्लेयर बनो, नहीं तो रिजर्व में बिठा देंगे। उन्होंने कहा कि चाहे आप कितने भी बडे हों, पार्टी से बडा कोई नहीं है। दरअसल पिछले लंबे समय से पंजाब की लीडरशिप कई खेमों में बंटी हुई है। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद, जहां पार्टी को 13 में से 7 सीटों पर जीत मिली, पांच नगर निगमों में पार्टी ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को अच्छी लड़ाई दी और चार बड़े नगर निगमों में उन्हें सत्ता में काबिज होना मुश्किल कर दिया, लेकिन लुधियाना पश्चिमी के दौरान फूट खुलकर सामने आई। पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच की जंग खुलकर सामने आई। इसके चलते कांग्रेस की सबसे मजबूत स्थिति वाली सीट पर आशू को हार का मुंह देखना पड़ा। पार्टी स्पष्ट रूप से यहां खेमों में बंटी नजर आई। एक खेमे में पार्टी प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा आदि नजर आए तो दूसरे खेमे में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, राणा गुरजीत सिंह, परगट सिंह और भारत भूषण आशू सरीखे नेता नजर आए।

तरनतारन उपचुनाव में भी नहीं दिखी एकजुटता

पिछले दिनों पार्टी के एक खेमे ने विधायकों और पिछला चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से हस्ताक्षर करवाकर एक मुहिम चला दी गई, जो सीधे तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी को स्पोर्ट कर रही थी। हालांकि, चन्नी एक जगह मात खा गए, जहां पार्टी के एससी विंग की एक रैली के दौरान कह दिया कि पार्टी ने अनुसूचित जातियों को कोई पद नहीं दिया हुआ है। पार्टी का प्रधान, विपक्ष का नेता, महिला विंग और यूथ विंग के प्रधान पद एक ही वर्ग को दिए हैं। उनके इस बयान का खासा विरोध हुआ। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के सीनियर नेताओं को दिल्ली बुलाकर डांट लगाई और हस्ताक्षर अभियान चलाने वालों को फटकार सुननी पड़ी।

लुधियाना में फैक्ट्री मालिक ने फंदा लगाकर दी जान

दो दिन पहले ही गांव से लौटा था, कमरे में लटका मिला शव, यूपी का रहने वाला था

लुधियाना।

लुधियाना के हैबोवाल इलाके की कुंज विहार कॉलोनी में शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक 26 वर्षीय फैक्ट्री मालिक ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अमिताभ यादव के रूप में हुई है। अमिताभ पिछले तीन साल से लुधियाना में लेडीज सूट पर कढ़ाई (एम्ब्रॉयडरी) का कारोबार कर रहा था। जानकारी के मुताबिक घटना दोपहर करीब 4 बजे की है। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जब किसी काम से ऊपर बने कमरे में गए तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो कर्मियों ने किसी तरह दरवाजा खोला। अमिताभ का शव फंदे से लटक रहा था। बताया जा रहा है कि अमिताभ यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और उसका पूरा परिवार गांव में ही रहता है। वह अभी दो दिन पहले ही अपने परिवार से मिलकर लुधियाना वापस लौटा था। घर से आने के तुरंत बाद उठाए गए इस खौफनाक कदम से हर कोई हैरान है। फिलहाल सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना हैबोवाल के साह्न किशन लाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर कब्जे में लिया और सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। हमें दोपहर बाद सूचना मिली थी कि एक युवक ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयानों के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा।

जीत के बावजूद पाकिस्तान बाहर, नेट रन रेट ने तोड़ा सेमीफाइनल का सपना

नई दिल्ली। शनिवार को कैंडी के पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सुपर 8 ग्रुप 2 के मैच में श्रीलंका को 147 रन से नीचे रोकने में असफल रहने के बाद पाकिस्तान टी20 विश्व कप 2026 की दौड़ से बाहर हो गया है। इस मुकाबले का नतीजा मायने नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को पछाड़कर क्वालीफाई करने के लिए 65 रनों से अधिक की जीत का अंतर बनाए रखना था। श्रीलंका के 147 रन का आंकड़ा पार करने के साथ ही न्यूजीलैंड सुपर 8 ग्रुप 2 से इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सुपर 8 ग्रुप 1 से दक्षिण अफ्रीका पहले ही शीर्ष चार में जगह बना चुका है, और कोलकाता में भारत बनाम वेस्टइंडीज का मैच अंतिम सेमीफाइनलिस्ट का फैसला करेगा। पाकिस्तान ने शनिवार को यहां सुपर आठ चरण के मैच में श्रीलंका के खिलाफ पांच रन से जीत दर्ज की लेकिन नेट रन रेट में न्यूजीलैंड से पिछड़ने केकारण टी20 विश्व कप से बाहर हो गया। सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (100) के शतक और फखर जमां के (84 रन) के अर्धशतक तथा दोनों के बीच किसी भी विकेट के लिए टी20 विश्व कप इतिहास में 176 रन की रिकॉर्ड भागीदारी से आठ विकेट पर 212 रन बनाए।

इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 207 रन बनाए जिसमें कप्तान दासुन शनाका ने नाबाद 76 रन और पवन रत्नायके ने 58 रन की अर्धशतकीय पारी खेलीं। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने बड़ा स्कोर बनाने के लिए आक्रामक बल्लेबाजी की लेकिन श्रीलंका के मैदान पर खराब प्रदर्शन ने प्रतिद्वंद्वी टीम को फायदा पहुंचाने में योगदान दिया। जमां 16वें ओवर में आउट हुए, उन्होंने दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए 42 गेंद की पारी खेली जिसमें नौ चौके और चार छक्के जड़े थे। जब वह 15 रन पर थे तो दासुन शनाका की गेंद पर महीश तीक्षणा के हाथों से निकलकर एक चौका लग गया।

जब वह 46 रन पर थे तब श्रीलंकाई विकेटकीपर ने कैच लेने की जोरदार अपील की लेकिन टीम ने डीआरएस नहीं लिया। फरहान (60 गेंद में नौ चौके, पांच छक्के) ने धमाकेदार बल्लेबाजी की पहल की जिससे पाकिस्तान ने पांचवें ओवर के अंदर 50 रन का आंकड़ा पार किया। इससे उन्हें हर ओवर में कम से कम 10 रन बनाने की लय मिली जिसे उन्होंने अच्छी तरह बनाए रखा।

अशोका एक्सप्रेस
राष्ट्रीय हिन्दी समाचार-पत्र

प्रिय पाठक, विज्ञापन दात्ता,
आप अपने क्षेत्र की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य तथा धार्मिक लेख, कविता एवं कार्टून लिख भेजें। व्हाट्सएप या ईमेल पर आपके द्वारा भेजी गई सामग्री सुव्यवस्थित ढंग से प्रकाशित किया जायेगा।
नोट: पूर्व प्रकाशित लेखो को न भेजे।
संपादक: विजय कुमार
Website: https://ashokaexpress.com/, Email:-ashoka.express@live.com, Mobile No. 9810674206

अशोका एक्सप्रेस को आर्थिक योगदान भी कर सकते है।

Account Holder Name : ASHOKA EXPRESS
Bank Account No. : 10650995502 & 41856402452
IFSC Code : SBIN0004846
UPI ID : 9810674206@sbi

केजरीवाल-सिसोदिया ने हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चना, आबकारी केस में कोर्ट ने किया था आरोप मुक्त

नई दिल्ली । राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट को खारिज कर दिया है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोप तय करने से इनकार करते हुए बरी कर दिया। अदालत ने सीबीआई के आरोपों को अपर्याप्त, विरोधाभासी और बिना ठोस सबूतों के बताते हुए जांच एजेंसी की साजिश थ्योरी को कमजोर करार दिया। इस फैसले के बाद आज केजरीवाल और सिसोदिया ने पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पहुंचकर पूजा-अर्चना की। मामले की शुरुआत 2022 में हुई थी, जब सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में कथित अनियमितताओं की जांच शुरू की। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (आरोपी-8) और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (आरोपी-18) समेत अन्य ने निजी शराब कारोबारियों के साथ मिलीभगत कर नीति को प्रभावित किया, जिससे करोड़ों रुपये का अवैध लाभ हुआ। सीबीआई की मुख्य चार्जशीट और चार पूरक चार्जशीट्स में कुल 23 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, के. कविता और अन्य शामिल थे। आरोप थे कि नीति में बदलाव से थोक विक्रेताओं को 12त्न मार्जिन दिया गया, जो कथित तौर पर रिश्वत के रूप में साझा किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज जितेंद्र सिंह ने कहा, ऐसा लगता है कि जांच पूर्वनिर्धारित दिशा में आगे बढ़ी, जिसमें नीति बनाने या कार्यान्वयन से जुड़े लगभग हर व्यक्ति को फंसाया गया, ताकि अन्यथा कमजोर कहानी को गहराई और विश्वसनीयता का भ्रम दिया जा सके। कोर्ट ने कहा, रिकॉर्ड पर रखी सामग्री का मूल्यांकन ऐसी जांच पद्धति को उजागर करता है,

जिसके जरिये कानूनी रूप से स्वीकार्य सामग्री के अभाव में बड़ी व जटिल साजिश का आभास पैदा करने की कोशिश की जाती है। कोर्ट ने हिदायत दी, अनुमान एवं धारणा की जगह जांच एजेंसियों को निष्पक्षता के साथ सिर्फ प्रामाणिक एवं ठोस साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे दायर करने चाहिए। 598 पन्नों के आदेश में कोर्ट ने कहा, मामला आपराधिक अभियोजन की बुनियादी शर्तों को भी पूरा नहीं करता। ऐसे में आरोपी संख्या 1 से 23 को सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है। इनमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू भी शामिल हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में सीबीआई की हजारों पन्नों की चार्जशीट को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूरी तरह खारिज कर दिया। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने 598 पेज के अपने आदेश में कहा कि मुख्य चार्जशीट (24 नवंबर 2022) और चार पूरक चार्जशीटों में अपराध का एक भी ठोस सबूत नहीं है। अदालत ने सीबीआई जांच को विरोधाभासी और हेरफेर से भरी बताते हुए जांच अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की। जज ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि दस्तावेज गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते, अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। इसमें कोई आपराधिक साजिश का साक्ष्य नहीं मिला। अदालत ने सुनवाई के दौरान एजेंसी पर कई बार नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि हजारों पेजों में पेश तथ्य गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते। फैसले में जेल में बिताए समय पर भी टिप्पणी की। अदालत ने नोट किया कि मनीष सिसोदिया करीब 530 दिन जेल में रहे, जबकि अरविंद केजरीवाल दो बार के अंतराल में 156 दिन हिरासत में थे। केजरीवाल को 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में जमानत दी थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रस्तुत दस्तावेज चार्जशीट से मेल नहीं खाते। आरोप तय करने पर 12 फरवरी 2026 को फैसला सुरक्षित रखा गया था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कविता कल्वाकुंटला उर्फ के. कविता, दुर्गेश पाठक, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मूथा गौतम, समीर महेंद्रू, अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे, बुच्चिबाबू गोरंटला, राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद कुमार सिंह, चनप्रीत सिंह रायत, कविता कल्वाकुंटला उर्फ के. कविता, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष चंद माथुर और सरथ चंद्र रेड्डी। जज ने विशेष रूप से कुलदीप सिंह को आरोपी नंबर 1 बनाने पर आश्चर्य जताया और सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की।

सचाई की जीत, तानाशाही की हार, कोर्ट के फैसले के बाद बोली आप, कहा- पार्टी कट्टर ईमानदार

नई दिल्ली ।

आम आदमी पार्टी ने कहा कि तथाकथित दिल्ली आबकारी घोटाला मामले को खारिज करने वाली सीबीआई की विशेष अदालत का ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है. यह आम आदमी पार्टी को खत्म करने के इरादे से बीजेपी से साठगांठ करने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए भी तमाचा है. पार्टी ने कहा, अदालत का 598 पन्नों का फैसला इस मामले को मुकदमे के लायक भी नहीं मानता है. यह पार्टी के उस लगातार स्टैंड को सही साबित करता है कि यह मामला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जेल भेजने की एक गहरी साजिश थी. यह अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों की ईमानदार छवि को खराब करने की एक हताश कोशिश थी. उनकी गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर पार्टी को तोड़ने की साजिश रची गई थी. आप ने आगे कहा, इस ऐतिहासिक फैसले ने मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की झूठ और राजनीतिक दुश्मनी पर आधारित गंदी राजनीति को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है. वे अपने उन राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करना चाहते थे जिन्हें मोदी और उनके साथी चुनावों या जनता की अदालत में नहीं हरा सकते थे. पार्टी ने कहा, कोर्ट के फैसले ने पहले से ही दागदार केंद्रीय एजेंसियों की साख को और भारी ठेस पहुंचाई है. ये एजेंसियां अपने राजनीतिक आकाओं की सेवा करने के लिए अपनी पेशेवर ईमानदारी से पूरी तरह समझौता कर चुकी हैं. वे बेशरमी से एक राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही हैं. आबकारी मामले में सीबीआई पर की गई टिप्पणियों से साफ है कि देश की इस प्रमुख जांच एजेंसी को इतना बदनाम करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. आप ने कहा, अदालत के फैसले से मोदी जी की बीजेपी के साथ-साथ कांग्रेस भी पूरी तरह बेनकाब हो गई है. यह कांग्रेस ही थी जिसने काल्पनिक आरोपों के साथ इस मनगढ़ंत मामले की शुरुआत की थी. आम आदमी पार्टी को राजनीतिक रूप से खत्म करने की गुप्त सहमति के तहत इसे बीजेपी को सौंप दिया गया था. पार्टी ने दावा किया, फैसले को पढ़ने से यह साफ हो जाता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के गुर्गे बेहद अक्षम साबित हुए. उन्हें बड़े पैमाने पर झूठ गढ़कर अरविंद केजरीवाल सरकार को अस्थिर करने का काम सौंपा गया था. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और उनके करीबी पूर्व मुख्य सचिव नरेश कुमार को आज भी अपने दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए कोई शर्म नहीं होगी. लेकिन उनके आकाओं को यह समझना चाहिए कि यह टीम बेहद औसत दर्जे की थी. उनके द्वारा सीबीआई को परोसा गया झूठ अदालत में आरोप पत्र के संज्ञान की सीमा भी पार नहीं कर सका. आप ने यह भी दावा किया, अदालत ने अपने फैसले में जोर देकर स्पष्ट किया है कि कोई भी आपसी लेन-देन नहीं हुआ था. किसी भी संस्था या व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था. तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ किसी भी गलत काम से जोड़ने का कोई सबूत नहीं था.

क्लीन चिट मिलते ही केजरीवाल का केंद्र पर हल्ला बोल, जंतर-मंतर पर महा-रैली की तैयारी

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 1 मार्च को जंतर-मंतर पर एक रैली का नेतृत्व करेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दिल्ली में हजारों कर्मचारियों की कथित बर्खास्तगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी की राय इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने यह जानकारी दी। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली के लोग भाजपा सरकार के जनविरोधी फैसलों से परेशान हैं और केजरीवाल की ओर रुख कर रहे हैं। भारद्वाज ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल उन हजारों कर्मचारियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। इसलिए, सभी बस मार्शल, डीटीसी बस कंडक्टर, मोहल्ला क्लिनिक कर्मचारी, डीआईएमटीएस कर्मचारी और अस्पतालों में काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटरों को अपनी-अपनी वर्दी पहनकर जंतर-मंतर पहुंचना चाहिए। 1 मार्च को आम आदमी पार्टी जंतर-मंतर पर एक विशाल रैली का आयोजन करने जा रही है, जिसमें हमारे समर्थक बड़ी संख्या में शामिल होकर हमें और अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद देंगे। मोहल्ला क्लीनिक से निकाले गए डॉक्टर और नर्स तथा 10,000 बस मार्शल (जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी) भी रैली में शामिल होंगे। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ, उन कंडक्टरों, बस मार्शलों, डॉक्टरों और फार्मासिस्टों की ओर से मुद्दे उठाएंगे जो अपनी वर्दी में आएंगे। अरविंद जी ने इनके लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को ''न्यायिक जांच में बिल्कुल भी खरा नहीं उतरने वाला'' मामला आगे बढ़ाने के लिए शुक्रवार को कड़ी फटकार लगाई तथा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य को आबकारी नीति मामले में आरोपमुक्त कर दिया। मामले में आरोपमुक्त किये गए लोगों में तेलंगाना जागृति की प्रमुख के. कविता भी शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह द्वारा फैसला सुनाये जाने के कुछ घंटों बाद, सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इसे चुनौती देते हुए अपील दायर की। निचली अदालत द्वारा जांच एजेंसी की कड़ी आलोचना किये जाने के जवाब में सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया या उन पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया। इस मामले ने केजरीवाल को लगभग राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया था और अदालत के फैसले में 'क्लीन चिट' मिलने की खबर आते ही उन्होंने राहत महसूस की। आरोपमुक्त होने पर भावुक नजर आ रहे केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला स्वतंत्र भारत के इतिहास की ''सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश'' थी।

उदय भानु को मिली जमानत, कांग्रेस बोली- अंततः न्याय की जीत हुई, हमें भरोसा था

नई दिल्ली । भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के अध्यक्ष उदय भानु चिब के पिता ने शनिवार को अपने बेटे को जमानत दिए जाने के लिए न्यायपालिका को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे न्यायिक व्यवस्था में उनका भरोसा और मजबूत हुआ है। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को चिब को जमानत दे दी, जिन्हें 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' में हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। चार दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद चिब को रात करीब एक बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट वंशिका मेहता के सामने पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट से चिब की हिरासत सात दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया, हालांकि, अदालत ने यह आग्रह ठुकरा दिया और उसे जमानत दे दी। चिब के पिता हरि सिंह ने न्यायपालिका को धन्यवाद देते हुए कहा, ''मैं न्यायपालिका का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगर कहीं से न्याय मिल सकता है, तो वह न्यायपालिका ही है।'' हरि सिंह भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उनके बेटे के खिलाफ आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से संबंधित धाराओं सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा, ''उनपर इतने सारे आरोप लगाए गए थे कि उनके लिए जमानत मिलना नामुमकिन था। हालांकि, जब अदालत ने मामले की जांच की और वास्तविकता को देखा, तो पाया कि मामले में कोई ठोस सबूत नहीं है।'' उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने चिब के मोबाइल फोन की पूरी तरह से जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। उन्होंने कहा, ''इसके बावजूद, उन्होंने (पुलिस ने) रात एक बजे फिर से सात दिन की रिमांड मांगी, लेकिन न्यायाधीश ने न्याय किया। मैं आशावान और अत्यंत आभारी हूं। उदय को जमानत देने के लिए मैं अदालत का धन्यवाद करता हूं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कानून ने अपना काम किया है। मीर ने कहा, ''हमेशा कहा जाता है कि कानून अपना काम करता है।

वास्तव में, कानून ने अपना काम किया है। हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। अंततः न्याय की जीत हुई है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि चिब को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया और एक मामले में फंसाया गया। मीर ने कहा, ''हमें न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।

ईरान तनाव से कच्चे तेल के वैश्विक बाजार में हलचल?

नई दिल्ली । पश्चिम एशिया की भू-राजनीति में आया नया उबाल वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए खतरे की घंटी बन गया है। अमेरिका और इस्राइल की ओर से ईरान के सैन्य और शीर्ष नेतृत्व के ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में प्रमुख युद्ध अभियानों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। इस सैन्य टकराव के बीच दुनिया भर की निगाहें होर्मुज जलडमरूमध्य पर टिक गई हैं, जिसके बाधित होने की आशंका से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल का खतरा पैदा हो गया है। आइए समझते हैं कि यह पूरा संकट क्या है और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा।

तेल कंपनियों ने अचानक शिपमेंट क्यों रोकी?

रिपोर्टों के अनुसार, कई बड़ी तेल और ट्रेडिंग कंपनियों ने सुरक्षा जोखिम बढ़ने के बाद होरमुज जलडमरूमध्य से ईंधन और कच्चे तेल की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी है। एक प्रमुख ट्रेडिंग कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनके जहाज फिलहाल कुछ दिनों तक आगे नहीं बढ़ेंगे। यह फैसला संभावित हमलों और समुद्री सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। यूरोपीय संघ के नौसैनिक मिशन एस्पाइड्स के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि क्षेत्र में संचालित जहाजों को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से वीएचएफ रेडियो संदेश मिल रहे हैं, जिसमें चेतावनी दी गई है कि किसी भी जहाज को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति नहीं है। अधिकारी के अनुसार तेहरान ने अभी तक इस तरह का कोई आदेश जारी करने की औपचारिक पुष्टि नहीं की है। ईरान ने बार-बार चेतावनी दी है कि अगर इस्लामी गणराज्य पर हमला होता है तो वह संकरे जलमार्ग को बंद कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है?

इससे नीचे दिए गए तथ्यों से समझिए।

होरमुज जलडमरूमध्य अरब प्रायद्वीप और ईरान के बीच स्थित दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग माना जाता है। हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल और अन्य ईंधन इसी रास्ते से वैश्विक बाजार तक पहुंचता है। यदि यहां आवाजाही लंबे समय तक प्रभावित होती है तो तेल की कीमतों में तेज उछाल और वैश्विक आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य क्या है और यह ऊर्जा बाजार के लिए इतना अहम क्यों है?

होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी के प्रवेश द्वार पर स्थित एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है, जो उत्तर में ईरान और दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात व ओमान के बीच स्थित है। यह वैश्विक ऊर्जा व्यापार की एक जीवन रेखा है, क्योंकि दुनिया का लगभग एक-चौथाई समुद्री तेल व्यापार इसी रास्ते से होता है।

सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक जैसे ओपेक (ओपीईसी) सदस्य एशियाई बाजारों तक पहुंचने के लिए इसी मार्ग पर निर्भर हैं।

कतर भी अपनी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के निर्यात के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करता है।

खाड़ी क्षेत्र क्यों माना जाता है वैश्विक आर्थिक केंद्र?

खाड़ी देश अंतरराष्ट्रीय निवेश और वित्तीय गतिविधियों के बड़े केंद्र हैं।

यहां दुनिया भर से लाखों प्रवासी कामगार काम करते हैं।

बड़े व्यापारिक शहर और ऊर्जा बाजार इसी क्षेत्र में केंद्रित हैं।

वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्ग से गुजरता है।

किसी भी सैन्य तनाव का असर सीधे विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

अगर ईरान इस रास्ते को बंद करता है, तो कच्चे तेल की कीमतों पर क्या असर होगा?

केप्लर लिमिटेड के विश्लेषकों के अनुसार, यदि ईरान केवल एक दिन के लिए भी इस रास्ते को ब्लॉक करता है, तो कच्चे तेल की कीमतें 120 डॉलर से 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। तुलनात्मक रूप से, इस साल 20 फरवरी तक वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का औसत मूल्य 66 डॉलर प्रति बैरल था। इस मार्ग के लंबे समय तक बंद रहने से ऊर्जा कीमतों में भारी उछाल आएगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगेगा।

क्या ईरान के लिए इस जलडमरूमध्य को पूरी तरह बंद करना संभव है?

ईरान के लिए इसे पूरी तरह बंद करना इतना आसान नहीं है। हालांकि ईरान ने अतीत में धमकियां दी हैं, लेकिन उसने कभी इसे पूरी तरह से बंद नहीं किया है क्योंकि इससे पश्चिमी नौसेनाओं की कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ईरान खुद भी अपने तेल निर्यात के लिए इसी मार्ग पर निर्भर है, इसलिए इसे बंद करने से उसकी अपनी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा।

इससे चीन के साथ उसके संबंध खराब हो सकते हैं, जो ईरानी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और संयुक्त राष्ट्र में उसका एक अहम सहयोगी है।

हालांकि, ईरान छोटी गश्ती नौकाओं, समुद्री बारूदी सुरंगों, ड्रोन हमलों या इलेक्ट्रॉनिक (जीपीएस) हस्तक्षेप के जरिए इस मार्ग पर व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा जरूर पैदा कर सकता है।

क्या यह भू-राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हो सकती है?

विशेषज्ञ मान रहे हैं कि खाड़ी देशों को निशाना बनाए जाने से सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि भू-राजनीतिक संतुलन भी बदल सकता है। यदि संघर्ष लंबा खिंचता है तो ऊर्जा आपूर्ति, निवेश प्रवाह और अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हालात शांत होंगे तो दुनिया की आर्थिक और रणनीतिक व्यवस्था किस रूप में सामने आएगी।

भारत के लिए यह संकट कितनी बड़ी चिंता का विषय है?

यह भू-राजनीतिक संकट भारत के लिए एक सीधा आर्थिक खतरा है। भारत अपनी कच्चे तेल की मांग का लगभग 90त्र हिस्सा आयात करता है। भारत की 40त्र कच्चे तेल की खरीद मध्य पूर्वी देशों (इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत) से होती है और इसका अधिकांश हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से ही होकर आता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत पहले ही रूस से तेल आयात कम कर रहा है, इसलिए यदि होर्मुज मार्ग बाधित होता है, तो रूस से आयात बढ़ाना एक आसान विकल्प नहीं होगा।

बाजार और निवेशकों में क्यों बढ़ी बेचैनी?

तेल आपूर्ति रुकने की आशंका से वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई है। ऊर्जा कीमतों में संभावित उछाल से परिवहन, उद्योग और व्यापार पर असर पड़ सकता है। निवेशक स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं क्योंकि पश्चिम एशिया में अस्थिरता का असर वैश्विक आर्थिक वृद्धि पर भी पड़ सकता है।

प्रवासी आबादी और व्यापार पर क्या असर?

खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था बड़ी संख्या में विदेशी कामगारों और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों पर आधारित है। यदि तनाव बढ़ता है तो लोगों की आवाजाही, व्यापारिक गतिविधियां और निवेश परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। इससे वैश्विक श्रम बाजार और वित्तीय प्रवाह पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। मौजूदा स्थिति को कई विशेषज्ञ संभावित वैश्विक बदलाव की शुरुआत मान रहे हैं। यदि ऊर्जा मार्ग सुरक्षित नहीं रहते तो दुनिया वैकल्पिक सप्लाई चेन और नए रणनीतिक गठबंधन तलाश सकती है।

क्या ग्रीन स्टील का इस्तेमाल होने से कार्बन उत्सर्जन हो रहा कम?

नई दिल्ली । सरकारी परियोजनाओं में 26 प्रतिशत ग्रीन स्टील का इस्तेमाल अनिवार्य होने से साल 2030 तक 20.9 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जा सकता है। अगर ग्रीन स्टील की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत हो जाए तो इसके बाद 29.7 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचा जा सकता है। यह हर वर्ष लगभ 90 लाख कारों को सड़कों से हटाने के बराबर है। यह जानकारी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई व क्लाइमेट कैटालिस्ट की ओर से गुरुवार को जारी आकलन रिपोर्ट में आए हैं। सीआईआई के कार्यकारी निदेशक और ग्लोबल इकोलेबलिंग नेटवर्क बोर्ड के अध्यक्ष के. एस. वेंकटगिरी ने कहा कि ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट भारत के इस्पात क्षेत्र को कम कार्बन उत्पादन की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्लाइमेट कैटालिस्ट की निदेशक साक्षी बलानी ने कहा, ग्रीन स्टील को लेकर एक मजबूत आदेश भारत के इस्पात क्षेत्र को किसी भी सब्सिडी या तकनीकी प्रोत्साहन से तेज गति से बदल सकता है। ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट ही कार्बन उत्सर्जन घटा सकता है, बड़े पैमाने पर निवेश खोल सकता है। अगर इस्पात मंत्रालय साल 2028 में 26 प्रतिशत खरीद अनिवार्य कर दे तो 93 प्रतिशत इस्पात कंपनियां प्रमाणित ग्रीन स्टील के लिए तैयार है। अभी सार्वजनिक खरीद पर प्रतिवर्ष लगभग 45-50 लाख करोड़ रुपये खर्च कर लगभग 3.16 करोड़ टन स्टील की खपत होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, मेट्रो रेल परियोजनाएं और रेल परियोजनाओं में ग्रीन स्टील के उपयोग से परियोजना लागत केवल 0.2 प्रतिशत से 1.2 प्रतिशत तक बढ़ती है। ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट इस दशक में भारत के इस्पात क्षेत्र की जलवायु महत्वाकांक्षाओं को ठोस और मापने योग्य कार्रवाई में बदलने का सबसे प्रभावी साधन है।

आरबीआई का सख्त कदम- ब्रोकर फंडिंग पर 100 फीसदी कोलैटरल अनिवार्य

मुंबई । बैंकिंग और कैपिटल मार्केट से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ब्रोकर फंडिंग को लेकर सख्त रुख अपनाया है। नए निर्देशों के तहत बैंकों को शेयर ब्रोकरों या ब्रोकिंग संस्थाओं की दी जाने वाली फंडिंग के बदले 100 प्रतिशत कोलैटरल लेना अनिवार्य किया है। यानी अब जितनी राशि का फंडिंग एक्सपोजर होगा, उतना ही पूरी वैल्यू का सुरक्षा गिरवी (कोलैटरल) रखना जरूरी होगा। यह कदम बाजार में बढ़ते लीवरेज, ब्रोकिंग जोखिमपूर्ण ट्रेडिंग और संभावित डिफॉल्ट की आशंका को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। हाल के वर्षों में डेरिवेटिव्स और मार्जिन ट्रेडिंग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे वित्तीय स्थितरता पर दबाव की चिंता बढ़ी थी।

ब्रोकिंग कंपनियों से आप क्या समझते हैं?

ब्रोकिंग कंपनियां वे वित्तीय संस्थान होती हैं जो शेयर बाजार में निवेशकों के लिए खरीदी और बिक्री की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए बीच के माध्यम की भूमिका निभाती हैं। ये कंपनियां सेबी या संबंधित नियामक संस्थाओं के तहत पंजीकृत होती हैं और निवेशकों को शेयर, बॉन्ड, डेरिवेटिव और कमोडिटी में ट्रेडिंग की सुविधा देने के लिए प्लेटफॉर्म

उपलब्ध कराती हैं। इसके बदले वे ब्रोकरेज या कमीशन शुल्क वसूलती हैं।

कोलैटरल क्या होता है?

कोलैटरल वह संपत्ति या सुरक्षा होती है, जिसे कोई व्यक्ति या संस्था लोन या फंडिंग के बदले गिरवी रखती है। जब आप बैंक से पैसा लेते हैं, तो बैंक अपने जोखिम को कम करने के लिए बदले में कोई गारंटी मांगता है यही कोलैटरल कहलाता है।

यह फैसला क्यों लिया गया है?

आरबीआई का मानना है कि पार्याप्त कोलैटरल से बैंकों का जोखिम कम हो गया और सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी। इसे लेकर आरबीआई ने 13 फरवरी को वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण सुविधा संशोधन के दिशा निर्देशों को जारी किया था। इसमें पूंजी बाजारों के मध्यस्थों (सीएमआई) को ऋण सुविधा से जोड़ा गया है। यह संशोधन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। हालांकि बैंकों के पास इसे पहले अपनाने का विकल्प भी दिया गया है।

ब्रोकिंग कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा?

रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल ने इन बदलावों के असर के बारे में विश्लेषण करते हुए बताया है कि, यह बदलाव बैंकों को ब्रोकिंग कंपनियों व प्रोप ट्रेडिंग को दी जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं के बारे में निर्देश देता है। ये यह भी बताता है कि सीएमएस को कोई भी क्रेडिट सुविधा देते समय, बैंकों को किस सीमा तक और किस तरह के कोलैटरल रखना होगा। हमारा अनुमान है कि इस फैसले का सीधा असर उन ब्रोकिंग कंपनियों पर पड़ेगा, जो बैंकों से उधार लेकर ग्राहकों को मार्जिन फंडिंग देती थीं। अब उन्हें अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था करनी होगी या फिर अपने लेंडिंग मॉडल में बदलाव करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे शॉर्ट-टर्म में ट्रेडिंग वॉल्यूम पर असर पड़ सकता है, खासकर हाई-लीवरेज सेगमेंट में। हालांकि लंबी अवधि में यह कदम बाजार को अधिक स्थिर और सुरक्षित बनाने में मदद कर सकता है।

प्रोप ट्रेडिंग के लिए क्या निर्देश?

आरबीआई के दूसरे बड़े फैसले के तहत बैंकों को प्रोपाइटरी ट्रेडिंग के लिए सीधे फंडिंग देने पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। प्रोप ट्रेडिंग वह व्यवस्था है, जिसमें कोई ब्रोकिंग फर्म या वित्तीय संस्था अपने ही पैसे से बाजार में ट्रेड करती है ताकि मुनाफा कमा सके। जब इस तरह की गतिविधियों के लिए बैंक फंडिंग का इस्तेमाल होता है, तो जोखिम और बढ़ जाता है क्योंकि बाजार में उतार-चढ़ाव का सीधा असर बैंकिंग सिस्टम पर पड़ सकता है। इसी जोखिम को देखते हुए आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंकों का पैसा सट्टा आधारित गतिविधियों में नहीं लगाया जाना चाहिए।

फर्जी बिल बनाकर आइटीसी वसूलने वाला आरोपी गिरफ्तार

करीब 200 करोड़ रुपये की फर्जी बिल ट्रेडिंग कर जीएसटी चोरी करने का अंदेशा

मुरादाबाद।

एसआइटी (अपराध शाखा) ने फर्जी बिल बनाकर आइटीसी वसूलने वाले गैंग के मुख्य आरोपी को आगरा से गिरफ्तार किया है। करीब 200 करोड़ रुपये की फर्जी बिल ट्रेडिंग कर जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह के आगरा मधुनगर सदर बाजार नई आबादी ताल फिरोज खान निवासी पुनीत को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से दस्तावेज, इलेक्ट्रानिक उपकरण और बैंकिंग सामग्री बरामद की गई है।इस प्रकरण में रा'यकर विभाग रेंज-बी मुरादाबाद के प्रधान सहायक आदित्य प्रताप सिंह ने अल जजा ट्रेडर्स के विरुद्ध 1.20 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी ने यह काम वर्ष 2019 में शुरू किया था। दिल्ली में सिद्दीक नाम के व्यक्ति ने खाते खुलवाने के बाद फर्जी जीएसटी फर्मों के माध्यम से बिल ट्रेडिंग का नेटवर्क शुरू किया। उसकी पत्नी, बेटी और अन्य लोगों के नाम से फर्में बनाकर बिना माल की वास्तविक आपूर्ति किए केवल पोर्टल पर बिल अपलोड किए जाते थे। इन फर्मों के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) लेकर रकम विभिन्न खातों में घुमाई जाती और बाद में नकद निकासी कर कमीशन काटकर संबंधित व्यक्तियों को दे दी जाती थी। जांच में सामने आया कि आरके इंटरनेशल, मेघना इंटरप्राइजेज, वानया इंटरप्राइजेज के खातों से करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ। आरोपी पुनीत ने बताया कि करीब 200 करोड़ रुपये के फर्जी बिल घुमाए गए थे। यह सभी लकड़ी कारोबार के लिए बिल बनाए थे। पुलिस ने आरोपी के पास से 11 मोबाइल फोन (सात की-पैड, चार एंड्रॉयड), 12 एटीएम कार्ड, 29 चेक बुक, आधार व पैन कार्ड, 32 किरायानामा, नौ टैक्स इनवाइस, पांच मुहरें, एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, दो बिल्टी बुक समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। साथ ही खातों में मौजूद छह लाख रुपये सीज किए गए हैं। एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि इस प्रकरण में अल जजा इंटरप्राइजेज के नाम पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसकी तलाश और सर्विलांस टीम ने इस फर्जी ट्रेल को पकड़ा है। बाकी की भी तलाश की जा रही है।

'बारगाहे खुदाबंदी में गुनाहों की माफी के लिए मांगे दुआएं'

माह-ए-रमजान का दूसरा अशरा शुरू

मुरादाबाद।

मुकद्दस रमज़ान माह को तीन अशरों में बांटा गया है। पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफिरत और तीसरा जहन्नुम से निजात का होता है। शनिवार को 10 रोजे पूरे होने के बाद ख्बाबरकत माह-ए-रमजान का पहला अशरा पूरा हो गया। पहला अशरा रहमत का होता है। इसी के साथ रविवार से दूसरा अशरा शुरू हो गया जो कि मगफिरत का है। दूसरे अशरे में अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगना सबसे अफजल माना गया है। रमज़ान के पहले अशरे में रोजेदारों ने रहमत की दुआओं के साथ इबादत की, अब दूसरे अशरे में वो मगफिरत यानी गुनाहों से माफी की दुआएं मांगने के साथ इबादत करेंगे। दरगाह हजरत शाह मौहम्मद इस्हाक मियां रह. के स÷ादानशीन हाजी मौहम्मद इकबाल इस्हाकी बताते हैं कि पूरे रमजानुल मुबारक के महीने में खुदा की रहमत है। यह अजमत व बरकत वाला महीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बरकत वाले मुबारक

हाजी इकबाल इस्हाकी

महीने को तीन अशरा में बांटा है। एक रोजा से दस रोजा तक पहला अशरा है, पहला अशरा खुदा की रहमत वाला होता है। इस अशरे में खुदा की रहमत नाजिल होती है। 11 रोजा से दूसरा अशरा शुरू होता है, जो रविवार से शुरू हो गया है। इस अशरा में खुदा ए पाक अपने बंदों की मगफिरत करते हैं। यानी अल्लाह पाक अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमाते हैं। इस अशरा में हमें चाहिए की बारगाहे खुदावंदी में गुनाहों की माफी के लिए मगफिरत करें। अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल करने वाला रहमान है। 21वें रोजे से तीसरा अशरा शुरू होता है। तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से निजात का है। इस अशरा में अल्लाह रब्बुल इ'जत अपने बंदों को जहन्नुम की आग से बचाते हैं. रमजानुल मुबारक का हर पल बहुत खास है।

रमजान का महीना हमें वक्त की पाबंदी का आदत डालता है। रमजानुल मुबारक में वक्त पर सोना, उठना, नमाज अदा करना, सेहरी इफ्तार करना भी इबादत है. रमजान के महीने में फिरता, जकात, सदका जितना तकसीम की जाये, उतना अच्छा है।

इस महीने में सत्तर गुना सवाब अधिक मिलता है। रोजेदार को इफ्तार कराने का बड़ा सवाब है. कोई भी रोजेदार भूखा नहीं, पड़ोसी को इस का ख्याल रखना चाहिए।

सतत उद्यमिता के लिए नवाचार, नैतिकता, सहयोग अनिवार्य

मुरादाबाद। तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी-टिमिट के आईएसटीडी मुरादाबाद चैप्टर के तत्वावधान में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार प्रेरित उद्यमिताः सतत विकास के लिए रणनीतियों पर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के कैंपस में हुई आईएसटीडी की पहली राष्ट्रीय संगोष्ठी में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा, नवाचार, नैतिकता, सहयोग और संस्थागत समर्थन के जरिए ही भारत जैसे उभरते देशों में सशक्त और सतत उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सकता है। टिमिट के ×00 से अधिक छात्रों की उत्साही सहभागिता के बीच रिसर्च पेपर्स बेस्ड एसडीजीएस एंड इन्नोवेशनः एंटरप्रिन्यूरियल स्ट्रेटेजीज़ एंड स्टार्टअप परसेप्टिपस पुस्तक का विमोचन भी हुआ। इससे पूर्व दीप प्र'जवलन के संग मेडिकल एलटी में राष्ट्रीय संगोष्ठी का श्रीगणेश हुआ। अतिथियों का बुके और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। संचालन स्टुडेंट पर्व जैन ने किया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के प्रबंधन अध्ययन संस्थान की पूर्व निदेशक प्रो. संगीता जैन ने बतौर विशिष्ट अतिथि कहा, यद्यपि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अत्यंत सक्षम तकनीक है, फिर भी अंतिम निर्णय मानवीय विवेक और दूरदर्शिता पर आधारित होना चाहिए। साथ ही उन्होंने सलाह दी, एआई का उपयोग मजबूत नैतिक चिंतन और उत्तरदायी व्यवहार के साथ किया जाए ताकि नवाचार समाज के व्यापक हित में हो। प्रो. जैन ने कहा, स्पष्टता, सहयोग और विश्वसनीयता को सफल एआई-आधारित उद्यमों की आधारशिला है। मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के व्यवसाय प्रबंधन संस्थान के डॉ. सिद्धार्थ जैन ने कहा, स्टार्टअप्स की स्थिरता के लिए रणनीतिक योजना, जोखिम आकलन और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन अनिवार्य हैं। उद्यमिता में तनाव प्रबंधन की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रो. जैन ने कहा कि अनिश्चितताओं और दबाव के बीच संतुलित निर्णय, धैर्य और लचीलापन दीर्घकालिक सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्टार्टअप के लिए निरंतर सीखने, प्रतिक्रिया स्वीकार करने और स्वयं को अनुकूलित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में डॉ. चंचल चावला, डॉ. सतेन्द्र आर्य, डॉ. विभोर जैन, डॉ. मोहित रस्तोगी, डॉ. राजीव वर्मा, डॉ. प्रतिभा शर्मा, डॉ. चारुल वर्मा, दीप्ति वर्मा,अंशु चौहान आदि की मौजूदगी रही।

कोर्ट ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश

पीड़ित पक्ष की तरफ से आसिफ एडवोकेट ने पेश की दलीलें

फतेहपुर।

अपर सिविल जज (सी. डि.)/एसीजेएम कोर्ट संख्या-1, ललिता यादव ने पीड़ित पक्ष को सुना और संबंधित थाने को आदेशित किया है कि आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति तत्काल न्यायालय को भी प्रेषित की जाए। विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद आसिफ ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित हसन इमाम स्व.अली इमाम निवासी-ग्राम बहरा सादात थाना सुल्तानपुर घोष के माता-पिता गांव में ही रहते थे। पिता अल्जाइमर बीमारी से ग्रसित थे। गांव का लवकुश सिंह जोकि भू-माफिया और अपराधी किस्म का व्यक्ति है जिसके ऊपर पहले से कई मुकदमे

पंजीकृत हैं। धोखाधड़ी करके पीड़ित के पिता से दो बीघा जमीन अपने साथी के नाम बैनामा करा लिया। उसके बाद उस जमीन को अपनी पत्नी के नाम वापस बैनामा करा लिया और जब इसकी शिकायत हसन इमाम ने संबंधित पुलिस से की तो इस बात से वह नाराज हो गया और हसन इमाम को रास्ते पर घेर कर गाली गलौज की और मारा पीटा तथा धमकी दी की उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत किया तो जान से मार देंगे। भू-माफिया ने 7000 रुपए भी छीन लिए थे। उक्त घटना के संबंध में सुल्तानपुर घोष पुलिस को शिकायती पत्र दिया। लेकिन पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। तब पीड़ित कोर्ट की शरण में आया और 27 फरवरी 2026 को अपर सिविल जज ललिता यादव की अदालत ने वाद को सुना और सुल्तानपुर घोष पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक मामला पंजीकृत कर रिपोर्ट की एक प्रति न्यायालय को भी प्रेषित करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता ने कहा कि ऐसे आदेश से समाज में न्याय का संदेश जाता है।

एम एस पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव की रही धूम

बच्चों की प्रस्तुति ने लोगों का मनमोहन, बच्चों ने बिखेरा जलवा

मेजा प्रयागराज। प्रयागराज के मेजा स्थित एम एस पब्लिक स्कूल का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रामनगर दलई का पूरा स्थित एम एस पब्लिक के प्रांगण मे किया गया। इसका उद्देश्य विद्यालय के छात्रों की प्रतिभा, परिश्रम और कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करना है। कार्यक्रम के आयोजक सोभनाथ सिंह यादव व मुख्य अतिथि के रूप में मेजा विधायक संदीप पटेल व विशिष्ट अतिथि एस डी पब्लिक के प्रबंधक नीरज यादव रहे। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गयी। इन प्रस्तुतियों में भारतीय संस्कृति, देशभक्ति और सामाजिक संदेशों का समावेश रहा। यह आयोजन बच्चों की कलात्मक क्षमताओं को निखारने और उन्हें मंच प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मेगा विधायक संदीप पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहें। विद्यालय प्रबंधक शोभनाथ यादव ने क्षेत्रवासियो व अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के समस्त स्टाफ और एम एस पब्लिक स्कूल के प्रबंधक तथा प्रधानाचार्य शशि प्रकाश यादव मनीष,द्वारा किया गया है। एस डी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक नीरज यादव ने कहा की ÷बच्चों की मुस्कान और उनकी कला ही भविष्य की नींव है।इस नींव को अपने स्नेह से सींचें। इस आयोजन में विजय राज यादव मुकेश शर्मा संकट यादव सहित कई लोग उपस्थित रहे।

रोमी में अज़ीमुश्शान सिद्दीकी ने सभों को दी दावते इफ्तार – जाबिर हुसैन सिद्दीकी

मुस्लिम समाज में दावत देने का रिवाज बहुत आम है, लेकिन कुछ दावतें ऐसी होती हैं जो दीनदारी (धार्मिकता) की बुनियाद पर होती हैं। ये दावतें धर्मपरायणता, आपसी एकता, भाईचारा, लगाव और सद्भाव की ओर इंसान के दिलो-दिमाग को ले जाती हैं। हाल ही में अपने निवास पर अजीम-उल-शान सिद्दीकी ने शानदार दावत-ए-इफ्तार देकर इस बात को साबित कर दिया है कि दावतें सिर्फ शादी, अकीका या वलीमा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इफ्तार की दावत देना भी धर्मपरायणता, आपसी मेल-मिलाप और एकता की एक शानदार मिसाल है। पिछले दिनों अजीम-उल-शान सिद्दीकी ने अपने निवास पर विशेष इफ्तार दावत का आयोजन कर यह संदेश दिया कि- आपकी आर्थिक स्थिति जो भी हो, वह मायने नहीं रखती। यदि आपके दिल में अपनों के लिए प्यार और भाईचारा है, तो लोगों को अपने दस्तरख्वान पर बुलाएं। एक साथ इफ्तार करें और मग़रिब की नमाज़ अदा करें ताकि यह खूबसूरत परंपरा आम हो सके। इससे हर इंसान के दिल में रमजान शरीफ की महानता और महत्व स्थापित हो जाता है। इस आयोजन में लोगों ने जमात के साथ नमाज पढ़ी और मेजबान ने आने वालों का शुक्रिया अदा किया। इस तरह की दावतों से तेरा-मेरा का फर्क मिट जाता है। भाइयों के बीच जो नफरत, ईर्ष्या या कड़वाहट का माहौल कभी-कभी बन जाता है, वह खत्म होकर प्यार और तालमेल में बदल जाता है। अल्लाह तआला हमें ऐसी दावतें करने की तौफीक दे, ताकि हम साबित कर सकें कि हम केवल वलीमा या अकीका करना ही नहीं जानते, बल्कि अपने घरों पर इफ्तार आयोजित कर समाज के हर वर्ग को साथ बिठाने का जज्बा भी रखते हैं। रमजान की असली गरिमा तभी उजागर होती है जब हम अपनों को पहचानें और सबको एक साथ दस्तरख्वान पर बैठने का मौका दें। मुख्य अतिथि-इस दावत में मुख्य रूप से मोहम्मद इमरान सिद्दीकी, नवाब सिद्दीकी, कारी अब्दुल लतीफ कादरी, सैयद आरिज़ रज़ा, सैयद फ़िरोज़ हसन, सैयद शारिक रज़ा आदि शामिल रहे।

जम्मू-कश्मीर में क्रिकेट का नया सूरज, रणजी ट्रॉफी जीतकर मनाया जश्न, पीएम मोदी ने दी बधाई

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जम्मू और कश्मीर टीम को उनकी पहली रणजी ट्रॉफी जीत पर बधाई दी और उनके असाधारण साहस, अनुशासन और जुनून की सराहना की। जम्मू और कश्मीर ने 67 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए शनिवार को हुबली में खेले गए रणजी ट्रॉफी के फाइनल में मजबूत टीम कर्नाटक को हराया। पीएम मोदी ने एक पोस्ट में लिखा कि जम्मू और कश्मीर टीम को उनकी पहली रणजी ट्रॉफी जीत पर बधाई! यह ऐतिहासिक जीत टीम के असाधारण साहस, अनुशासन और जुनून को दर्शाती है। यह जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए गर्व का क्षण है और वहां के बढ़ते खेल प्रेम और प्रतिभा को उजागर करता है। आशा है कि यह उपलब्धि कई युवा खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने और अधिक खेलने के लिए प्रेरित करेगी। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कर्नाटक के खिलाफ

ऐतिहासिक पहली रणजी ट्रॉफी जीत के लिए जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई दी है। सिन्हा ने इस उपलब्धि को केंद्र शासित प्रदेश के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के असाधारण प्रदर्शन और समर्पण की सराहना की। सिन्हा ने पत्रकारों से कहा कि जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम ने रणजी टूर्नामेंट में बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन किया है। टीम को मेरी शुभकामनाएं। एक्स पर एक पोस्ट में उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर का गौरवशाली क्षण आ गया है! हमारी क्रिकेट टीम को रणजी ट्रॉफी जीतते हुए देखकर मेरी भावनाएं शब्दों से परे उमड़ रही हैं। उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से इतिहास रचा- पूरे केंद्र शासित प्रदेश की ओर से आपको धन्यवाद, हम गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं। आपने इतिहास को अमर कर दिया है - इसे सम्मान के साथ अपनाएं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 के बाद केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई खेल क्रांति के लिए आभारी हूं। सभी युवाओं से- इस जोश को अपने क्षितिज को प्रज्वलित करने दें- अथक और लगन से प्रशिक्षण लें। इस जीत को आधार बनाकर प्रभुत्व के युगों का नेतृत्व करें - जम्मू-कश्मीर का अजेय भविष्य आपसे शुरू होता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में जीत के बाद जम्मू और कश्मीर क्रिकेट टीम को बधाई दी और इसे दृढ़ता और लगन का एक उल्लेखनीय उदाहरण बताया। पारस डोगरा के नेतृत्व वाली जम्मू और कश्मीर टीम ने 67 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए मजबूत टीम कर्नाटक को हराया। अपने पहले रणजी फाइनल में खेलते हुए, जम्मू और कश्मीर ने पहली पारी में 291 रनों की विशाल बढ़त के दम पर खिताब जीता। यह बढ़त आठ बार की चैंपियन कर्नाटक टीम के लिए नामुमकिन साबित हुई, जिसकी कप्तानी देवदत्त पडिक्कल कर रहे थे। शाह ने अपने खाते पर न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि पर्दे के पीछे काम करने वाली पूरी टीम की सराहना की। उन्होंने लिखा कि जम्मू-कश्मीर की भारतीय टीम को उनके दृढ़ संकल्प और लगन की अद्भुत कहानी के लिए हार्दिक बधाई। खिलाड़ी प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर के कोचिंग स्टाफ, प्रबंधन और प्रशासकों के योगदान को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को संभव बनाने के लिए पर्दे के पीछे अथक परिश्रम किया है। मुझे विश्वास है कि यह जीत इस क्षेत्र की वर्तमान पीढ़ी के दिलों में आत्मविश्वास जगाएगी और आने वाली पीढ़ी को बल्ला या गेंद उठाने के लिए प्रेरित करेगी। हमारा खेल दुनिया भर में प्रेरणा की ऐसी कहानियों से समृद्ध है, और मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को भी उतना ही सम्मान मिलेगा।

न्यूजीलैंड या इंग्लैंड? सेमीफाइनल में किससे होगी टीम इंडिया की टक्कर! समझें पूरा गणित?

नई दिल्ली। आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में सेमीफाइनल मुकाबले का सिनेरियो लगभग तय हो गया है. सुपर-8 के दूसरे ग्रुप में सभी मुकाबले खेले जा चुके हैं. इस ग्रुप से इंग्लैंड के अलावा न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया है. इंग्लैंड अपने तीनों मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर रही है. ऐसे में सेमीफाइनल में इंग्लैंड की टक्कर पहले ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम से होगी. वहीं न्यूजीलैंड अब भारत या फिर वेस्टइंडीज में से किसी एक से टकराएगी. बता दें कि न्यूजीलैंड ग्रुप-2 से 3 अंक के साथ बेहतर रनरेट के कारण सेमीफाइनल में पहुंची है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल की रेस में थी, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में उसे कम से कम 65 रन से मैच जीतना था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया. पाकिस्तान ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाए थे. इस स्कोर के बचाव में पाकिस्तान श्रीलंकाई टीम को 147 रन पर रोकना था, लेकिन उसके गेंदबाज ऐसा नहीं कर पाए. सेमीफाइनल के समीकरण की बात करें तो ये तय हो गया है कि इंग्लैंड की टक्कर ग्रुप-1 में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम के साथ होगी. ऐसे में इंग्लैंड की टक्कर वेस्टइंडीज और भारत के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता टीम से होना तय है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये अहम मुकाबला 1 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स के मैदान पर होगा. इस मैच में जो भी टीम जीत हासिल करेगी वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. वहीं ग्रप-1 से साउथ अफ्रीका की टीम पॉइंट्स टेबल में बेहतर रन रेट के साथ पहले स्थान पर है. उसका आखिरी मैच जिम्बाब्वे के साथ है. अगर कुछ उलटफेटर नहीं हुआ तो साउथ अफ्रीका अपने तीसरे मैच को जीतकर पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर रहेगी. वहीं वेस्टइंडीज या फिर भारत दूसरे स्थान पर क्योंकि दोनों टीमें 1-1 मैच हारी है, जिसके कारण उसका रनरेट भी साउथ अफ्रीका से कम है. ऐसी स्थिति में साउथ अफ्रीका की टीम का सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के टकर होना तय है, जबकि वेस्टइंडीज या फिर भारत में से कोई एक इंग्लैंड से भिड़ेगी.

साहिबजादा फरहान ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, पाकिस्तान ने टी20 विश्वकप में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया

पल्लेकेले । सेमीफाइनल के लिए आखिरी बार जोर लगाने उतरी पाकिस्तान टीम ने दमदार प्रदर्शन किया।

इस मैच में टीम ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 212 रन बनाकर इतिहास रच दिया। यह उनका टी20 विश्व कप में सबसे बड़ा स्कोर है। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने भी विस्फोटक पारी खेलकर रिकॉर्ड्स की झड़ियां लगा दीं।

फरहान और फखर की रिकॉर्ड साझेदारी

इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बल्लेबाजी का न्योता दिया। साहिबजादा फरहान और फखर जमां ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाते हुए रिकॉर्ड 176 रनों की साझेदारी निभाई।

दोनों के बीच हुई यह साझेदारी पाकिस्तान के लिए श्रीलंका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे बड़ी है। इस दौरान साहिबजादा फरहान ने 59 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।

साहिबजादा का ऐतिहासिक शतक

फरहान टी20 विश्व कप के एक संस्करण में दो शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले उन्होंने नामीबिया के खिलाफ 100 रनों की नाबाद पारी खेली थी। वहीं, टी20 विश्व कप में दो शतक जड़ने वाले वह दूसरे बल्लेबाज बन गए। इससे पहले क्रिस गेल ने वैश्विक टूर्नामेंट में शतक जड़ा था। दिलचस्प बात यह है कि टी20 अंतरराष्ट्रीय में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम दर्ज है। उन्होंने इस प्रारूप में तीन सैकड़े ठोके हैं। साहिबजादा फरहान टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बन गए। इससे पहले 2014 में अहम शहजाद ने बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में 111 रनों की नाबाद पारी खेली थी। वहीं, फरहान एक टी20 विश्व कप संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने अब तक टी20 विश्व कप 2026 में 18 छक्के लगाए हैं। शिमरोन हेटमायर ने मौजूदा टूर्नामेंट में 17 छक्के लगाए हैं। फरहान के बाद फखर जमां ने 42 गेंदों में 84 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से नौ चौके और चार छक्के निकले। इस मैच में पाकिस्तान ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 212 रन बनाए, जो उनका टी20 विश्व कप में सर्वाधिक स्कोर है। इससे पहले टीम ने 2016 में बांग्लादेश के खिलाफ 201/5 का स्कोर बनाया था। श्रीलंका के खिलाफ बनाया गया यह स्कोर टी20 अंतरराष्ट्रीय में पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है। इससे पहले टीम ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ छह विकेट पर 232 रन बनाए थे।

विंडीज को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी! 10 साल पहले इसी टीम ने खिताब से किया था दूर; टूट गए थे करोड़ों दिल

कोलकाता । टी20 विश्व कप 2026 का सुपर-8 चरण रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। दो टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं जबकि दो स्थानों के लिए लड़ाई जारी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार यानी 01 मार्च को अहम मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लेगी। दोनों ही टीमों के लिए यह मैच करो या मरो की स्थिति जैसा है। हालांकि, टीम इंडिया विपक्षी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहेगी। मौजूदा टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज ग्रुप स्टेज में अजेय रही।

सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुरुवार को खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज को नौ विकेट से हार का सामना करना पड़ा, जबकि अपने पहले मैच में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को हराया था। वहीं, सुपर-8 का अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गंवाने वाली भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने मैच में 72 रन से जीत दर्ज की। रविवार को भारत-वेस्टइंडीज के बीच होने वाला मुकाबला क्वार्टर फाइनल की तरह है। भारतीय टीम अपने घर में खेलने के बावजूद वेस्टइंडीज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगी। इसकी वजह 2016 का टी20 विश्व कप सेमीफाइनल है जिसमें भारतीय टीम को वेस्टइंडीज ने सात विकेट से हराकर खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया था। 31 मार्च 2016 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए सेमीफाइनल में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने विराट कोहली के नाबाद 47 गेंद पर बनाए 89 रन की मदद से 2 विकेट पर 192 रन बनाए थे। लेंडल सिमंस के 51 गेंदों पर 5 छक्कों और 7 चौकों की मदद से खेली गई नाबाद 82 और आंद्रे रसेल के 20 गेंदों पर बनाए विस्फोटक 43 रनों की पारी के दम पर वेस्टइंडीज ने 19.4 ओवर में 3 विकेट पर 196 रन बनाकर न सिर्फ मैच जीता था बल्कि अपने घर में भारतीय टीम के विश्व कप जीतने का सपना तोड़ा था।

भारतीय घरेलू क्रिकेट में बदलाव की आहट, टी20 से रणजी तक नया इतिहास; 2025-26 सत्र बना यादगार

नई दिल्ली । भारतीय घरेलू क्रिकेट का 2025-26 सत्र इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। इस बार तीनों घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी में देश को नए चैंपियन मिले। टी20 में झारखंड, वनडे में विदर्भ और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में जम्मू-कश्मीर ने पहली बार खिताब जीतकर यह साबित कर दिया कि भारतीय घरेलू क्रिकेट में अब नई ताकतें उभर रही हैं। टी20 प्रारूप में झारखंड ने ईशान किशन की कप्तानी में कमाल कर दिया। फाइनल में हरियाणा के खिलाफ टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 262 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। ईशान किशन ने 49 गेंदों पर 101 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि कुमार कुशाग्र ने 81 रन बनाए। दोनों के बीच 177 रन की साझेदारी ने मैच का रुख पूरी तरह झारखंड की ओर मोड़ दिया। जवाब में 263 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरियाणा की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखी और 193 रन पर सिमट गई। झारखंड ने

69 रन से जीत दर्ज कर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम कर ली। वनडे में विदर्भ ने भी इतिहास रचा। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 317 रन बनाए। अथर्व तायडे ने 128 रन की शानदार शतकीय पारी खेली और यश राठौड़ ने उनका अच्छा साथ दिया। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए सौराष्ट्र की टीम ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन विदर्भ की सधी हुई गेंदबाजी के आगे 279 रन पर रुक गई। 38 रन की जीत के साथ विदर्भ ने पहली बार यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। सबसे बड़ी खबर प्रथम श्रेणी क्रिकेट से आई, जहां जम्मू-कश्मीर ने 91 साल के इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत ली। कर्नाटक के खिलाफ फाइनल मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी में 291 रन की बढ़त ने जम्मू-कश्मीर को चैंपियन बना दिया। टीम ने पहली पारी में 584 रन बनाए थे और दूसरी पारी में भी मजबूत बल्लेबाजी की। कामरान इकबाल और साहिल लोटरा की 197 रन की नाबाद साझेदारी ने कर्नाटक की उम्मीदें पूरी तरह खत्म कर दीं। मैच भले ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी की बढ़त के आधार पर जम्मू-कश्मीर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

संगठित अपराध में कड़ी कार्यवाही की जाये: अनिल कुमार

(वेबवार्ता)

मुरादाबाद। प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल कुमार की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में विकास कार्यों, निर्माण कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। समीक्षा बैठक में उद्यान अधिकारी तथा दुग्ध विकास के प्रबन्धक के अनुपस्थित रहने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी को संबंधित अधिकारियों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आगामी बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिकारी प्रत्येक कार्यदिवस में 10 से 12 बजे तक कार्यालय में बैठकर प्रभावी रुप से जनसुनवाई करें यह

शासन की सर्वो॔च प्राथमिकता है। अधिकारीगण सीयूजी नम्बर पर आने वाली फोन कॉल जरूर रिसीव करें और यदि व्यस्त हैं तो बाद में रिटर्न कॉल अवश्य करें। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि नये विकास कार्यो के प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध करा दें। प्रभारी मंत्री ने कहा कि संगठित अपराध में कड़ी कार्यवाही की जाये तथा साइबर क्राइम की घटनाओं में वृद्धि हुई है, इस पर निगरानी एवं सतर्कता रखी जायें। प्रभारी मंत्री ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए जानकारी प्राप्त की, उप निदेशक कृषि ने बताया कि किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत जनपद में ×42516 किसान लाभान्वित हुए है तथा फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 1419 को योजना से लाभान्वित किया गया है। जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि जनपद मुरादाबाद में नये गन्ना मूल्य भुगतान के अन्तर्गत 94.41 प्रतिशत का भुगतान हो चुका है।

मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में क्षमता को मज़बूत करने के लिए एआई स्किलिंग प्रोग्राम शुरू

चंडीगढ़। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गूगल और यूट्यूब के साथ मिलकर मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में क्षमता को मज़बूत करने के मकसद से पूरे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजें स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 के तहत शुरू की गई इस पहल का मकसद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्रिएटर्स, डेवलपर्स और मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए हाई-क्वालिटी एआई ट्रेनिंग तक पहुंच को आसान बनाना है। यह प्रोग्राम प्रीमियम कोर्स के लिए पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप देता है, जिससे पार्टिसिपेंट्स इंडस्ट्री से मान्यता प्राप्त सर्टिफ़िकेशन मुफ़्त में पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस कोर्स का पाठ्यक्रम दो खास लर्निंग ट्रैक पर बना है - फ़ाउंडेशनल एआई और प्रॉम्प्टिंग, जो क्रिएटिव आइडिया, स्टोरीटेलिंग और कंटेंट डेवलपमेंट के लिए जेनरेटिव एआई टूल्स के इस्तेमाल पर फ़ोकस करता है और जेनरेटिव एआई लीडर, जो प्रोफेशनल्स के लिए जेनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी की बिज़नेस वैल्यू और ज़िम्मेदारी से लागू करने को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि फेज़-वन पूरा होने पर प्रतिभागी फेज़-टू में आगे बढ़ने के लिए पात्र होंगे, जिसमें वर्टेक्स एआई , जेमिनी और गूगल क्लाउड जैसे एडवांस्ड टूल्स पर हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग दी जाती है, जो खास तौर पर मीडिया वर्कफ़्लो के लिए बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स और मीडिया प्रोफेशनल्स इस मौके का फायदा उठा सकते हैं।

कुरुक्षेत्र के मथाना में बनेगा जैविक कृषि व आधुनिक प्रबंधन प्रणाली संस्थान, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

चंडीगढ़।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कृषि विकास मेला लाडवा में घोषणा करते हुए बड़ी सौगातें दी हैं। गांव मथाना में 10 एकड़ भूमि पर जैविक कृषि व आधुनिक प्रबंधन प्रणाली संस्थान खोला जाएगा। इस संस्थान में कृषि साइंस के यूजी, पीजी से लेकर पीएचडी तक के कोर्स उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही कैथल से यमुनानगर वाया ढांड, पिपली, रादौर मार्ग को फोरलेन किए जाने की घोषणा की। यह फोरलेन मार्ग एनएच-152डी, एनएच-44 और शामली एक्सप्रेस-वे को जोड़ेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लाडवा उपमंडल सचिवालय के नए भवन, लोकनिर्माण विभाग की 9 सडक़ों का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से लाडवा अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि विकास मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर पर बैठकर विश्वविद्यालय व किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों और कृषि मेले का अवलोकन किया मुख्यमंत्री ने कृषि विकास मेला को हरियाणा की कृषि आत्मा का उत्सव बताया जो अन्नदाताओं के परिश्रम, संकल्प और नवाचार का महोत्सव है। मुख्यमंत्री ने भव्य आयोजन के लिए विश्वविद्यालय और सभी आयोजकों को बधाई व शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने होली के पर्व की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर

> संस्थान में होंगे कृषि साइंस के यूजी, पीजी से लेकर पीएचडी तक के कोर्स
>
> कैथल-ढांड-पिपली-रादौर-यमुनानगर तक सड़क होगी फोरलेन
>
> लाडवा में अब हर साल लगेगा कृषि विकास मेला
>
> मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा उपमंडल सचिवालय के नए भवन तथा 9 नई सडक़ों का किया शिलान्यास
>
> कृषि मेला ज्ञान, नवाचार और प्रेरणा का अनूठा संगम - मुख्यमंत्र

मुख्यमंत्री व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डा. बीआर काम्बोज ने स्मृति चिन्ह, शॉल व पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगतिशील किसानों ने नवाचारों से कृषि क्षेत्र को गति दी है, जो हमारे अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन गए हैं। इस मेले का थीम जल संरक्षण प्रति बूंद से अधिक फसल रखा गया है। मौजूदा समय में बदलते जलवायु परिदृश्य, घटते भूजल स्तर और अनियमित वर्षा ने कृषि क्षेत्र के सामने अनेक नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे समय में जल संरक्षण पर केंद्रित यह मेला वास्तव में दूरदर्शी पहल है। प्रति बूंद अधिक फसल का अर्थ तकनीक के

साथ हमारी सोच में परिवर्तन लाना भी है। उन्होंने कहा कि हमें समझना होगा कि पानी अनंत नहीं है। यह मेला किसानों को जल प्रबंधन की उन्नत तकनीकों से जोडक़र एक जन-आंदोलन का रूप लेगा।

वैज्ञानिक शोध को हर खेत व हर किसान तक पहुंचाएं

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक शोध को प्रयोगशाला तक सीमित न रखें, बल्कि हर खेत व हर किसान तक पहुंचाएं। किसान और वैज्ञानिक का सीधा संवाद ही कृषि को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। यह मेला किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों, उन्नत बीजों, नई तकनीकों और वैज्ञानिक सलाह से जोडऩे का एक सशक्त मंच है। यहां पर 150 से अधिक स्टॉल्स, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन, मिट्टी और पानी की जांच सुविधा, रोगग्रस्त फसलों की जांच व निदान, फसल प्रतियोगिता, लकी ड्रॉ, ये सब मिलकर इस मेले को ज्ञान, नवाचार और प्रेरणा का संगम बना रहे हैं। सरकार का दृष्टिकोण किसान को अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जा दाता, रोजगार दाता और अर्थव्यवस्था का निर्माता बनाना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारी पहचान हमारे खेत-खलिहानों से है, हमारी समृद्धि हमारे किसान के पसीने से है। हरियाणा की धरती ने हमेशा देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि ऊर्जा दाता, रोजगार दाता और अर्थव्यवस्था के निर्माता बने। इसलिए हमारी नीतियां केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि किसान की आय बढ़ाने, लागत घटाने और जोखिम को कम करने पर केंद्रित हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे किसान ऐसी फसलों की पैदावार लें, जिसमें पानी की कम जरूरत होती है। सरकार ने ऐसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी-मेरी विरासत योजना वर्ष 2020 में शुरू की। इस योजना के तहत वैकल्पिक फसलें लेने या खेत खाली छोड़ने वाले किसानों को 8 हजार रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत 2 लाख 20 हजार एकड़ में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोने पर किसानों को 157 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। इसके अलावा पानी की बचत के लिए वर्षा जल संचयन, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। माइक्रो इरीगेशन तकनीकों पर 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। किसानों को तालाब बनाने के लिए भी 85 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के शोधित पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की 27 योजनाएं तैयार की हैं। इनमें से 11 पूरी हो चुकी हैं। इनसे सिंचाई के लिए एक स्थायी जल स्रोत मिलेगा, नहरों पर दबाव कम होगा और भूजल का दोहन भी घटेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने फसल अवशेष व पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए किसानों को जागरूक किया है और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान हित में नकली बीज व कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित बीज व कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे नकली बीज व कीटनाशकों की रोकथाम में सहयोग करें।

'प्रयोगशाला से भूमि' तक नवाचार पहुंचाना है समय की मांग-राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर 2022, 2023 और 2024 के लिए चयनित 11 प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को 'हरियाणा विज्ञान रत्न' और 'हरियाणा युवा विज्ञान रत्न' पुरस्कारों से किया सम्मानित

चंडीगढ़।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आज राज भवन हरियाणा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने वर्ष 2022, 2023 और 2024 के लिए चयनित 11 प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को 'हरियाणा विज्ञान रत्न' और 'हरियाणा युवा विज्ञान रत्न' पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह केवल सम्मान समारोह नहीं, बल्कि ज्ञान, नवाचार और विज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति में हमारे सामूहिक विश्वास का यादगार क्षण है। राज्यपाल ने सभी सम्मानित वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां न केवल हरियाणा बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1966 में गठन के बाद से हरियाणा ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरित क्रांति के दौर में राज्य ने वैज्ञानिक कृषि, नवाचार और दृढ़ संकल्प के बल पर देश को खाद्य आत्मनिर्भरता दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। यही विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी नई और जटिल चुनौतियां लेकर आई है। सतत कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता हमारी विकास रणनीति का आधार बननी चाहिए। हमारा लक्ष्य सतत, समावेशी और प्रौद्योगिकी संचालित विकास सुनिश्चित करना है। राज्यपाल श्री घोष ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि शासन व्यवस्था और आम नागरिकों के जीवन में प्रत्यक्ष सुधार लाना चाहिए। अनुसंधान का वास्तविक माप उसके सामाजिक प्रभाव में निहित है। 'प्रयोगशाला से भूमि' और 'प्रयोगशाला से बाजार' के बीच की दूरी को कम करना आज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कि हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 'अटल टिंकरिंग लैब्स' और 'डिजिटल लैब्स' के जरिए विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अंबाला में बन रहा 'आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र' तथा कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला मेमोरियल प्लैनेटेरियम का आधुनिकीकरण वैज्ञानिक चेतना को सुदृढ़ करेगा।'कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना' के तहत अभियांत्रिकी विषयों में छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये तक की 250 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी, जबकि 'विज्ञान रत्न पुरस्कार' के तहत 5 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। राज्यपाल ने बताया कि 1983 में स्थापित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय राज्य में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है। यह निदेशालय वरिष्ठ माध्यमिक स्तर से लेकर उन्नत अनुसंधान तक छात्रवृत्तियां प्रदान करता है तथा सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान परियोजनाओं को 50 लाख रुपये तक के अनुदान से सहयोग देता है। प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत बनाए जाने के सपने को साकार करने में वैज्ञानिकों को रहेगा विशेष योगदान-शिक्षा मंत्री महीपाल ढांड इस अवसर पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। इस विजन को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों का भी विशेष योगदान रहेगा। भारतीय विज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैज्ञानिक परंपराओं में से एक रही है। प्राचीन काल में चिकित्सा विज्ञान में चरक और सुश्रुत, खगोल और गणित में आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, रसायन विज्ञान में नागार्जुन ने अतुलनीय योगदान दिया। उन्होंने कहा कि प्राचीन खोजें आधुनिक विज्ञान की नींव रही हैं। भारतीय विद्वानों ने खगोल, गणित, चिकित्सा, रसायन, वास्तुकला और यंत्र विज्ञान में ऐसे सिद्धांत स्थापित किए, जिनका प्रभाव भारत ही नहीं, बल्कि अरब और यूरोप तक फैला। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने विज्ञान और स्वास्थ्य क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियां दर्ज कीं। तेज़ी से परीक्षण और उपचार प्रोटोकॉल विकसित किए गए और कोवैक्सिन तथा कोविशील्ड जैसे सुरक्षित एवं प्रभावी टीकों का विकास हुआ। इन प्रयासों ने न केवल भारतवासियों की रक्षा की, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय में भारत की नेतृत्व क्षमता को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत ने हाल ही में India AI Impact Summit 2026 में वैश्विक मंच पर अपनी नेतृत्व क्षमता साबित की। 100+ देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया और वैश्विक एआई दिशा निर्देश पर साझा घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। यह सम्मेलन भारत को एआई नवाचार और वैश्विक सहयोग का प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करता है। इस अवसर पर राज्यपाल की धर्मपत्नी श्रीमती मित्रा घोष, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, राज्यपाल के सचिव श्री डीके बेहरा, विज्ञान एवं तकनीकी के निदेशक श्री राजीव रतन व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।